संपादकीय जागरण

शनिवार, 10 फरवरी, 2024 : माघ शुक्ल प्रतिपदा वि. 2080

विभूतियों के सम्मान से समाज स्वयं सम्मानित होता है

सर्वोच्च नागरिक सम्मान

मोदी सरकार ने अपने फैसले से एक बार फिर देश को चौंकाया। उसने एक साथ तीन हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की। इस बार यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान दो पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिंह राव के अतिरिक्त जाने-माने कृषि विज्ञानी एवं हरित क्रांति के सूत्रधार एमएस स्वामीनाथन को भी प्रदान करने की घोषणा की गई। यह इसलिए अनपेक्षित रहा, क्योंकि चंद दिनों पहले ही कर्पूरी ठाकुर और फिर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से विभूषित करने का फैसला लिया गया था। यह पहली बार है, जब एक वर्ष में पांच हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की गई। इस पर आश्चर्य नहीं कि 15 दिनों के अंदर पांच विभूतियों को भारत रत्न देने के फैसले के बाद इस तरह की मांग होने लगी है कि अमुक-अमुक को भी यह सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। यह मांग स्वाभाविक है, क्योंकि अपने देश में ऐसी हस्तियों की कमी नहीं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने के साथ सार्वजनिक जीवन में अमिट छाप और एक यादगार विरासत छोड़ी है। चूंकि मोदी सरकार ने यह प्रदर्शित किया है कि वह सम्मान प्रदान करने के मामले में अपनी राजनीतिक विचारधारा को आड़े नहीं आने देती और भिन्न विचार वाले दूसरों दलों के नेताओं को भी सम्मान देती है, इसलिए यह आस बढ़ी है कि आने वाले समय में उन हस्तियों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जो इस सर्वोच्च नागरिक सम्मान की अधिकारी मानी जाती हैं।

यह उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाले कर्पूरी ठाकुर एवं किसानों-मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले चौधरी चरण सिंह के साथ साहसिक आर्थिक सुधारों से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले नरसिंह राव को भारत रत्न देने की मांग एक लंबे समय से हो रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से कांग्रेस ने संप्रग सरकार का नेतृत्व करते समय उन्हें यह सम्मान देने की आवश्यकता नहीं समझी। अंततः इस आवश्यकता की पूर्ति मोदी सरकार ने की। मनमोहन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकी ? यह एक ऐसा प्रश्न है, जो कांग्रेस को परेशान करता रहेगा। अपनी इस परेशानी के लिए वह अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती, क्योंकि नरसिंह राव हर लिहाज से भारत रत्न के अधिकारी थे। पहले कर्पूरी ठाकुर, फिर चौधरी चरण सिंह और नरसिंह राव को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा पर यह जो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने इन नेताओं को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर अपने राजनीतिक हित भी साधे हैं, उसे पूरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी एक यथार्थ है कि सरकारें अपने तमाम फैसले राजनीतिक लाभ-हानि को ध्यान में रखकर भी करती हैं। प्रश्न यह है कि जो काम मोदी सरकार ने किया, वह अन्य सरकारें क्यों नहीं कर सकीं? ऐसा करने का अवसर तो उनके पास भी था।

आत्मविश्वास बनाम अविश्वास

सरकार को परास्त करने अथवा कमजोर करने की उम्मीद से विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव का अस्त्र उपयोग में लाता है। हरियाणा विधानसभा में प्रमुख विपक्ष कांग्रेस 20 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। कांग्रेस ने 24 विधायकों के हस्ताक्षर लेकर स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव भेजा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी आहवान किया है कि जो विधायक सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें। स्पष्ट है कि पूर्व सीएम को अपने अविश्वास पर स्वयं ही विश्वास नहीं है। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि भाजपा की अगुवाई वाली वर्तमान गठबंधन सरकार सत्ता के लिए आवश्यक संख्या बल के आधार पर इस प्रस्ताव को निराधार साबित करने में सक्षम है। इसके बावजूद कांग्रेस इस मूव से क्या साबित करना चाहती है, समझ से परे है।

विपक्ष कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती दे रहा है संख्या बल से मजबूत गठबंधन सरकार का आत्मविश्वास

उधर, गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आत्मविश्वास से लबरेज हैं। कारण कि 90 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तापक्ष को विश्वास के लिए 46 विधायकों के समर्थन की दरकार है। भाजपा के पास खुद के 40 जबकि प्रमुख सहयोगी जजपा के दस व एक हलोपा सहित सात में से छह निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। सीएम ने इससे पहले भी हर छह माह में अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी थी। यह आत्मविश्वास से भरी सरकार का विश्वास ही बोल रहा है। हां, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से एक-दूसरे को सुनने का अवसर जरूर मिलेगा। विपक्ष को चाहिए कि जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो सरकार को भी सुनने का धैर्य साथ लाए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या एससी-एसटी आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए?

आज का सवाल

क्या पाकिस्तान के चुनाव नतीजे वहां की सेना को साख को गिराने वाले हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

दोराहे पर खड़ा पाकिस्तान

हर्ष वी. पंत

यदि पाकिस्तानी सेना ने किसी तरह तिकड़म कर अपने मन की सरकार गठित करा दी तो भी उसकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली

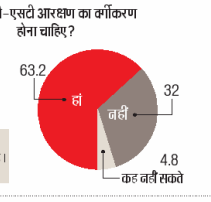

पाकिस्तान की तरह उसकी सेना के दिन भी इस समय बहुत अच्छे नहीं चल रहे। चुनाव नतीजे तो यही संकेत कर रहे हैं कि देश पर सेना की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसी भरी-पूरी आशंका है कि नतीजों को अपनी मंशा के अनुरूप मोड़ने के लिए सेना कोई भी तिकड़म कर सकती है। यह बात और है कि जनभावनाओं को नकारने से सेना के लिए जोखिम और बढ़ेंगे। अभी तक के चुनावी रुझान सेना के साथ ही पाकिस्तान के पारंपरिक स्थापित राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ा झटका हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि पाकिस्तान की असल कमान हमेशा सेना के हाथ में रही है। सेना समय-समय पर अपने फायदे के लिहाज से राजनीतिक मोहरे चुनती आई है। पिछले चुनाव में वह इमरान खान के पीछे खड़ी थी और तब इमरान पहली बार प्रधानमंत्री बनने में सफल भी हुए। फिर इमरान के साथ खटपट हुई तो उनके विरोधी दलों को एक मंच पर लाकर सेना ने उनकी गठबंधन सरकार गठित करा दी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान से तकरार जगजाहिर है और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के पूरे उपाय किए कि इमरान और उनकी पार्टी किसी भी सूरत में सत्ता की दहलीज तक न पहुंचे, लेकिन चुनावी रुझान उसके कुछ उलट दिख रहे हैं। अगर अंतिम परिणाम बहुत ज्यादा नहीं बदलते तो फिर यह सेना और अन्य दलों के लिए अपमान का कड़वा घूंट पीने जैसा होगा। स्थिति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे नवाज शरीफ एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए।

सेना ने इमरान खान को घेरने के लिए तगड़ी व्यूह रचना की थी। उन्हें तमाम मुकदमों में फंसा दिया गया। कुछ मामलों में उन्हें सजा भी हो गई। वह चुनाव लड़ने के लिहाज से अयोग्य हो गए। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआइ का चुनाव चिह्न 'क्रिकेट बैट' जब्त कर लिया गया। इसका अर्थ था कि पीटीआइ चुनाव में आधिकारिक उम्मीदवार उतारने की स्थिति में नहीं रही। इमरान की पार्टी के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। जो नेता बचे भी रह गए तो सेना के दबाव में उनकी सक्रियता सीमित रह गई। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी यदि पीटीआइ समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी इतनी भारी संख्या में जीतकर आ रहे हैं तो यह सेना और अन्य राजनीतिक दलों के लिए कड़ा संदेश है। यह न केवल इमरान खान की नैतिक जीत, बल्कि पाकिस्तान के चरित्र में आ रहे परिवर्तन का भी बड़ा संकेत है। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान की जनता सेना के राजनीतिक हस्तक्षेप और पारंपरिक राजनीतिक दलों के रवैये से निराश हो चुकी है। वह अपने पड़ोस में भारत को तरक्की करते हुए और विश्व की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित होते देख रही है। भारत में राजनीति जहां आरंभ से ही सैन्य प्रभाव से मुक्त रही है, वहीं इस समय जिस प्रकार भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति के विरुद्ध अभियान छिड़ा हुआ है, उसने भी पाकिस्तानी अवाम को कुछ हद तक प्रेरित करने का काम किया है। भारत के प्रति शत्रुता भाव के बावजूद पाकिस्तान में इंटरनेट मीडिया पर तमाम सामग्री प्रधानमंत्री मोदी की सराहना से भरी होती है। कई विश्लेषक मोदी की प्रशंसा में यह कहते हुए दिखते हैं कि वह अपने मुल्क को सही दिशा में ले जा रहे हैं।

अवधेश राजपूत

इस समय पाकिस्तान कई समस्याओं से जूझ रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो इसका असर अन्य मोर्चों पर भी पड़ रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि तालिबान भी उसे आंखें दिखा रहा है। ईरान ने तो कुछ दिन पहले एक प्रकार का हवाई हमला कर दिया, जिससे पाकिस्तान को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वहां सामाजिक एवं क्षेत्रीय स्तर पर तमाम विभाजन एवं विरोधाभास हैं। आंतरिक स्थायित्व नहीं है। यह सब देखकर पाकिस्तान की जनता का धैर्य जवाब दे रहा है। इसी कारण पाकिस्तान में सेना के संरक्षण वाले स्थापित शासन ढांचे से जनता का मोहभंग हुआ है। परिणामस्वरूप पाकिस्तान के इतिहास में यह चुनाव एक बड़े बदलाव का वाहक बनता दिख रहा है। लोकतंत्र की कुछ कोंपलें फूटती दिख रही हैं। इसका श्रेय इमरान को देना होगा। जहां पाकिस्तान के अलग-अलग राजनीतिक दल और नेता कुछ प्रांतों तक ही अपनी पहचान एवं असर रखते हैं, उसके उलट उन्होंने पूरे देश में अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया। उन्होंने सेना के खिलाफ खड़े होने का दमखम एवं जुझारूपन दिखाया कि वह किसी के आगे समर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ने से लेकर अमेरिकी हस्तक्षेप जैसे उन मुद्दों को उठाया जो आम पाकिस्तानियों को प्रभावित करने वाले रहे।

फिलहाल जो स्थितियां बन रही हैं उसमें यदि अंतिम परिणाम सेना की मंशा के अनुरूप नहीं रहे तो उसके लिए आगे की राह बड़ी चुनौतीपूर्ण होगी। पीटीआइ समर्थित निर्दलीय सरकार बनाने में सफल होते हैं या नहीं, यह तो अभी दूर की बात है। इतना जरूर है कि ऐसे नतीजे सेना और पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी एवं खतरे की घंटी के समान होंगे कि अब जनता सब कुछ बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। यदि किसी तरह सेना ने तिकड़म कर अपने मन की सरकार गठित करा दी तो भी उसके लिए दोराहे जैसी स्थिति होगी। ऐसी कोई भी सरकार कमजोर होगी और तब सेना पूरी तरह पर्दे के पीछे रहकर उसे संचालित नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में उसे सक्रिय भूमिका में आगे आना होगा। एक ऐसा देश जो आइएमएफ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ वित्तीय पैकेज की बाट जोह रहा हो, उसके लिए ये स्थितियां अनुकूल नहीं कही जाएंगी। सेना की सक्रिय भूमिका से जनता में उसकी छवि और साख के साथ ही स्वीकार्यता भी प्रभावित होगी।

ऐसे में पाकिस्तान को यदि मौजूदा चुनौतियों से निपटना है तो उन सुधारों का सूत्रपात करना होगा, जो उसे आवश्यक स्थायित्व एवं संतुलन प्रदान करने की ओर ले जाएं। यह तय है कि सेना और सियासत वहां अलग-अलग नहीं रह सकते, लेकिन उनकी सीमाएं तो तय ही की जा सकती हैं कि वे अपने-अपने दायरे में रहकर काम कर सकें। भारत के लिहाज से भी यही अनुकूल होगा कि वहां सेना और राजनीतिक वर्ग में टकराव के बजाय सुसंगति हो, तभी उसके साथ कोई सार्थक वार्ता की जा सकती है।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

भारत के तीन और रत्न

केसी त्यागी

चरण सिंह, नरसिंह राव और स्वामीनाथन ने अपनी-अपनी तरह से कमजोर वर्गों की जिंदगी बदलने का बड़ा काम किया

भारत ने समय-समय पर ऐसे व्यक्तियों का उदय देखा है, जिनके योगदान ने देश की प्रगति पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ऐसे ही एक दिग्गज नेता थे चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों का मसीहा भी कहा गया। उनकी राजनीतिक विरासत उन्हें भारत रत्न सम्मान देने का हकदार बनाती है। चौधरी चरण सिंह के साथ एक और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव को भी भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई। वह इस सम्मान के सच्चे हकदार थे, क्योंकि वह आर्थिक सुधारों के जनक और नायक थे। उन्होंने एक ऐसे समय देश की बागडोर संभाली थी, जब तमाम समस्याएं सिर उठाए खड़ी थीं। उन्होंने अल्पमत सरकार के बाद भी उन सभी समस्याओं का कुशलता से सामना किया और उल्लेखनीय सफलता हासिल की। तमाम चुनौतियों के बाद भी वह देश को आर्थिक बदहाली से बाहर निकाल कर प्रगति के पथ पर ले आए। यह अफसोस की बात है कि संप्रग के शासन काल में वह भारत रत्न के हकदार नहीं समझे गए। किसानों के मसीहा चरण सिंह और आर्थिक सुधारों के प्रणेता नरसिंह राव के साथ डा. एमएस स्वामीनाथन भी भारत रत्न से नवाजे जाएंगे। वह हरित क्रांति के जनक हैं। एक समय भारत में लगभग भुखमरी जैसे हालात थे और गेहूं, चावल, चीनी एवं दालें आदि वस्तुएं आयात करनी पड़ रही थीं। ऐसे कठिन समय में स्वामीनाथन ने कृषि क्रांति के जरिये कृषि क्षेत्र में एक स्वावलंबी भारत की आधारशिला रखी। आज हम गेहूं, चावल, चीनी आदि के सबसे बड़े निर्यातकों में हैं और अपने देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि यह स्थिति बन सकी तो इसमें स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान है। वह सच्चे अर्थों में भारत के रत्न हैं। चौधरी चरण सिंह, नरसिंह राव और एमएस स्वामीनाथन के योगदान में यह बात समान है कि इन तीनों ने अपनी-अपनी तरह से कमजोर तबकों का जीवन बदलने का काम किया। इन तीनों को भारत रत्न देने की मांग एक अर्से से हो रही थी। आखिरकार यह पूरी हुई।

चौधरी चरण सिंह किसान नेता इसीलिए कहलाए, क्योंकि उन्होंने सदैव किसानों की चिंता की और जब भी अवसर मिला, उनके हित में फैसले भी लिए। उनकी पहल से कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य किसानों के लिए उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना था, जो एक अभूतपूर्व कदम था। उनकी नीतियों ने न केवल किसानों की तात्कालिक चिंताओं को दूर किया, बल्कि एक आत्मनिर्भर और सशक्त कृषक समुदाय की नींव रखी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए वह किसी भी सीमा तक जाने को तैयार रहते थे। 1957 में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ तो उसमें पंडित नेहरू ने सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा। तब चरण सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। उन्होंने प्रस्ताव का विरोध किया। इससे पूर्व वह उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सरकार के राजस्व मंत्री के रूप में जमींदारी उन्मूलन कर काफी वाहवाही लूट चुके थे। चौधरी साहब ने बिंदुवार आधिकारिक प्रस्ताव का विरोध किया। वह भारतीय समाज की मानसिकता एवं कृषि भूमि के प्रति किसान के व्यक्तिगत लगाव पर धारा प्रवाह बोलते रहे। अधिवेशन में उपस्थित कार्यकर्ता करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते रहे। उनके भाषण की समाप्ति के बाद उक्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया।

पूरी हुई सर्वोच्च सम्मान की आस ● प्रतीकात्मक

उस समय कांग्रेस में पंडित नेहरू की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन चरण सिंह ने ऐसा किया। वास्तव में वह कृषि और किसानों की स्थिति कहीं अच्छे से समझते थे। चौधरी चरण सिंह सामाजिक न्याय के भी प्रतीक थे। वह समतावादी सिद्धांतों में दृढ़विश्वास रखते थे। दलित और हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकारों की वकालत करते थे। जब वह गृहमंत्री बने तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना की। उन्हीं की पहल पर केंद्र सरकार ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें यह प्रविधान था कि यदि तय समय में कोई चीनी मिल किसानों के पैसे का भुगतान नहीं करती तो सरकार के पास उस मिल के अधिग्रहण का अधिकार होगा, ताकि मिल चलाकर किसानों का बकाया दिया जा सके।

जैसे ही हम चौधरी चरण सिंह के जीवन और विरासत पर विचार करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका योगदान उनके राजनीतिक जीवन की सीमाओं से परे है। कृषि में उनकी दूरदर्शी नीतियां और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उन्हें एक उत्कृष्ट नेता की तरह पेश करते हैं। जिस लचीलेपन और दृढ़संकल्प के साथ उन्होंने ग्रामीण और कृषि परिदृश्य से संबंधित मुद्दों को निपटाया, वह उनके राजनीतिक कौशल को दर्शाता है। देश के नेताओं के बीच चौधरी चरण सिंह एक ऐसे पथप्रदर्शक के रूप में खड़े दिखते हैं, जिनका योगदान पीढ़ी-दर-पीढ़ी याद किया जाता है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना उन मूल्यों को मान्यता देना है, जिनके लिए और विशेष रूप से किसान हित के लिए वह खड़े रहे।

भारत रत्न का अर्थ उन व्यक्तियों को सम्मानित करना होता है, जिन्होंने किसी न किसी रूप में राष्ट्र की प्रगति में असाधारण योगदान दिया हो। भारत की कृषि नीतियों को आकार देने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में चौधरी चरण सिंह की भूमिका इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के मानदंडों के साथ सहजता से मेल खाती है। निःसंदेह यही बात पीवी नरसिंह राव और एमएस स्वामीनाथन पर भी लागू होती है। इन तीनों ने अपने कार्यों से देश पर गहरी छाप तो छोड़ी ही, एक ऐसी विरासत भी छोड़ गए, जो भावी पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करने वाली है।

(लेखक पूर्व सांसद एवं चौधरी चरण सिंह विचार मंच के अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

वर्तमान की महत्ता

काल की अनवरत बहती नदी में भूत और भविष्य का कोई भौतिक मान नहीं है, किंतु कालखंड का वह भाग जिसमें सक्रिय रहकर कर्म करके कुछ मान प्राप्त कर सकें वह वर्तमान कहलाता है। वर्तमान नौका की उस पतवार की भांति है जो प्रतिक्षण नदी के जल को पीछे धकेलकर नाव को आगे बढ़ाती है। वह यह चिंता नहीं करती कि एक तट से वह कितनी दूर आ गई या दूसरे तट से अभी कितनी दूर है। वह तो सामने आए जल को धकेलती रहती है और आगे बढ़ती जाती है।

ध्यान और योग इसी वर्तमान को बरतने पर आधारित हैं। ध्यान की सभी प्रकार की विधियां भूत और भविष्य की समस्त चिंताओं को त्याग कर, मन को हर प्रकार के मानसिक उद्वेगों से रहित करके, समता में स्थित रहकर वर्तमान के क्षण के प्रति सजग रहना सिखाते हैं। गीता में उल्लेख भी है-समत्वं योग उच्यते।' वर्तमान के हर क्षण के प्रति जितना अधिक हम सजग हो जाते हैं, उतना ही अधिक हमारे जीवन से अनिश्चितता, अंधकार और अविश्वास के दोलन कम होते जाते हैं। जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसने काल पर नियंत्रण साध लिया। वस्तुतः, इस वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त कुछ भी अपने हाथ में नहीं है।

भूत का अस्तित्व नहीं है। भविष्य अभी दूर है, परंतु वर्तमान को जिस प्रकार दिशा देंगे वह एक दिन भविष्य का वैसा ही भवन खड़ा कर देगा। भूत के समस्त दोषों को मिटाने के लिए भी वर्तमान में कार्य करना आवश्यक है। प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति को मिली एक बड़ी सफलता उसके अतीत की सारी असफलताओं को धूमिल कर देती है। चकरी पर झूला झुलाने वाला व्यक्ति अपने सामने आई कुर्सी पर अपनी शक्ति लगाता है, न कि आगे जाने वाली कुर्सी पर और न पीछे जाने वाली कुर्सी पर। चकरी सही से चले इसलिए वह बस अपने सामने आई कुर्सी पर दृष्टि जमाए रहता है। इसी तरह जीवन के किसी भी लक्ष्य को वर्तमान में रहकर ही भेदा जा सकता है।

ट्विंकल तोमर सिंह

पाठकनामा

pathaknama@hir.jagran.com

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी रहे अभियान

'रंग लाएगा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में सुरेंद्र किशोर ने यह सही कहा है कि कैंसर से भी ज्यादा घातक भ्रष्टाचार देश को तबाह कर रहा है। इसीलिए भारत अब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई का मन बनाया। व्यापार में टैक्स चोरी को नियंत्रित करने के लिए जीएसटी का प्रविधान किया। सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता राशि को पहुंचाया गया। डिजिटल लेन-देन को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया गया। 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' के संकल्प के साथ भ्रष्टाचार में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जांच एजेंसियों को छूट दी गई। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से देश की आम जनता का खुश होना स्वाभाविक है। शायद इसीलिए जनता के आशीर्वाद से अपने दो सफल कार्यकाल पूरे करने के बाद मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के लिए आत्मविश्वास से भरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में इसे तीसरे पायदान तक पहुंचाने की गारंटी दी जा रही है। यह तभी संभव है जब देश के विकास में बाधक बने आर्थिक भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसके लिए आम जन को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

pandeyvp1960@gmail.com

जननायकों को भारत रत्न

देश के तीन पूर्व दिग्गजों को 'भारत रत्न ' देने का एलान कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस सहित आइएनडीआइए में जबर्दस्त सेंध लगाकर सभी आलोचकों की बोलती बंद कर दी है। दो पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत चौधरी चरण सिंह (आरएलडी), दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव (कांग्रेस) और हरित क्रांति के जनक डा. एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न खिताब से नवाजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है कि चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृहमंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी, उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई-बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। भारत सरकार डा.एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। बताते चलें कि आरएलडी को आइएनडीआइए का हिस्सा बनाने के लिए इसके सुप्रीमो जयंत चौधरी से बातचीत अंतिम दौर में थी मगर भारत रत्न के एलान के बाद भाजपा के साथ जाने के सवाल पर जयंत ने कहा अब किस मुंह से इसे इनकार करूं। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने कहा कि मैं 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार विशेषकर गांधी परिवार को दोषी मानता हूं, जब यूपीए सरकार केंद्र में सत्ता में थी, भारत रत्न तो दूर, कोई पुरस्कार भी नहीं मिला।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

धरातल पर दिख रहीं कामयाबियां

केंद्र सरकार ने आख़िरी सत्र समाप्त होते यूपीए की मनमोहन सरकार आर्थिक नीतियों पर श्वेत पत्र लाने का दांव खेला। कांग्रेस अन्याय काल बता रही है। कांग्रेस विकास चाहती ही नही है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं का रोना रोने वाली कांग्रेस क्या यह नही जानती है कि यूपीए के कार्यकाल में हजारों किसानों ने आत्महत्या की। आज सरकारी आंकड़ों में युवाओं को कोई गिले शिकवे नही है। मोदी द्वारा लांच की गई योजनाओं और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया की चमक में स्टार्टअप के जरिये घर मे खुशहाली पैदा कर रहे है। महंगाई की बात करने वाली कांग्रेस देश को जूठ परोसती है। 2014 में महंगे सिलेंडर की भेंट भाजपा को कांग्रेस ने दी थी। आज रोजगार बढ़ा है लोगो की आय बढ़ी है और सबसे अहम बात यह है कि देश की इकोनामी पांचवें स्तर पर आ गई है। कांग्रेस दस साल का हिसाब दिखाने के लिए तैयार हुई है। कांग्रेस को आजादी के बाद का हिसाब देश की जनता को देना चाहिए। बैंकों की हालत खराब थी। आज देश बुलंदियों पर है तो यह भारत का सौभाग्य है कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है। चारो दिशाओं में सुरक्षित भारत की कल्पना हर कोई कर रहा है। विदेशी धरती पर भारत की अर्थव्यवस्था की बात पर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर वार कर कांग्रेस अपने आप को गिरा रही है। ब्लैक पेपर कांग्रेस के लिए सटीक बैठता है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

X पोस्ट

चौधरी चरण सिंह जी को मिलने वाला भारत रत्न सम्मान देश के हर किसान-मजदूर का सम्मान है। देश के गांव-देहात में रहने वाली जनता को सम्मान है।

शाहिद सिद्दीकी@shahid_siddiqui

चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद जयन्त चौधरी ने राजग में जाने के सवाल पर यही कहा कि अब कसर ही क्या बची है। ऐसे ही किसी दिन अगर बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न मिल जाए तो शायद उद्धव ठाकरे भी यही कहते सुनाई पड़ें।

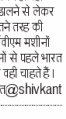

प्रभाष झा@prabhash_jha13

सरदार पटेल के बाद पीवी नरसिंह राव को मिला भारत रत्न सबसे सार्थक है। ये दोनों ही एक परिवार के सताए हुए रहे। राव को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार।

अभिजीत अय्यर मित्रा@Iyervval

पाकिस्तान की मतगणना में कैमरों के सामने हो रही धांधली सिद्ध करती है कि कागजी वोट डालने से लेकर जमा करने, गिनने और नतीजों तक कितने तरह की धांधली और लूट मचाई जा सकती है। ईवीएम मशीनों का विरोध करने वाले जानते हैं कि मशीनों से पहले भारत के चुनावों में ऐसी ही धांधली होती थी। वे वही चाहते हैं।

शिव कांत@shivkant

जनपथ

तरकश में उनके भरे तरह- तरह के तीर,
बिना लड़े ही ढेर हैं सभी चुनावी वीर।
सभी चुनावी वीर चौधरी या चौटाला,
देकर भारतरत्न फ्लैट सबको कर डाला।
देख अनोखी जंग खा रहे हैं सारे गश,
किंतु न खाली होय यहां मोदी का तरकश!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए : राहुल मित्तल द्वारा प्लाट नं. 15, इंडस्ट्रियल एस्टेट, दिल्ली रोड, हिसार से मुद्रित एवं प्रकाशित, सम्पादक (हरियाणा) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*, दूरभाष : 01662-282900, E-mail : hisar@hir.jagran.com -पं.सं. HARHIN/2007/22609 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद हिसार न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 17 अंक 257

****

अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ शनिवार, 10 फरवरी 2024

जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, किसी का सुख लूटने में नहीं।
- प्रेमचंद

हल्द्वानी में एक अतिक्रमण को ढहाने के विरोध में हिंसक भीड़ ने जिस खतरनाक व सुनियोजित ढंग से तेवर अपनाए उसकी पड़ताल जरूरी है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसकी आड़ में समाजविरोधी तत्व फायदा न उठा पाएं।

हल्द्वानी हिंसा की तपिश

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध मदरसे और धर्मस्थल को ढहाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय भीड़ ने जिस खौफनाक ढंग से सुनियोजित हमला किया, वह बेहद गंभीर मामला तो खैर है ही; यह एक बेहद संवेदनशील इलाके में चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान में पुलिस-प्रशासन की अधूरी तैयारियों को भी दर्शाता है। दरअसल, बृहस्पतिवार की शाम करीब चार बजे बनभूलपुरा क्षेत्र में एक अवैध मदरसे व धर्मस्थल को ढहाने के लिए पुलिस की सुरक्षा में नगर निगम की टीम पहुंची थी। अदालती आदेश था, अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन जैसे ही मशीनें आगे बढ़ीं, भीड़ ने पथराव चालू कर दिया। पेट्रोल बम और पत्थर के साथ भीड़ के तेवर इतने उग्र होंगे, शायद प्रशासन इसका अंदाजा नहीं लगा पाया। बनभूलपुरा थाने में आग लगाने के बाद बलवाइयों के तेवर इस कदर खतरनाक थे कि पुलिस की टीमों के सामने भागने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। छह लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा पुलिस व निगमकर्मी घायल हुए और 70 से अधिक वाहन फूंक दिए गए। पीएसी की दो कंपनियों और दो प्लाटून द्वारा मोर्चा संभालने के बाद अब स्थिति काबू में जरूर है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में खुफिया विभाग की नाकामी हैरान करती है। अगर सुबह सर्वे हुआ, तो शाम तक घरों की छतों पर इतने पत्थर कैसे इकट्ठे हो गए? एक संवेदनशील इलाके में कार्रवाई करने जा रहे पुलिसकर्मियों के पास न तो समुचित सुरक्षा उपकरण थे और न ही पर्याप्त हथियार। पहले कई मामलों में अलग-अलग प्रदेशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जब भीड़ ने प्रशासनिक अमले को कानूनी कार्रवाई करने से रोका है और हिंसक स्थितियां बनी हैं। हल्द्वानी ने उनसे कोई सबक नहीं लिया। यह पूरी घटना दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि उपद्रवी तत्वों ने यदि सुनियोजित हिंसा को अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है (जैसा कि प्रशासन का ताजा बयान है), तो वे इसे सामाजिक सद्भाव नष्ट करने की सीमा तक ले जाने की कोशिश भी कर सकते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के एक दिन बाद हुई इस घटना के बहाने सामाजिक ताना-बाना नष्ट करने की ताक में बैठे तत्व सफल न हो पाएं, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दोषियों को सख्त सजा और सामाजिक सद्भाव की रक्षा प्रशासन के यही दो लक्ष्य होने चाहिए।

सर्वोच्च सम्मान, कई संदेश

आर्थिक सुधारों, कृषि और कृषि विज्ञान क्षेत्र के दिग्गजों को देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से नवाज कर प्रधानमंत्री मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके राजनीतिक संदेश स्पष्ट हैं।

शेखर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

भारत रत्न का सम्मान दिए जाने और न दिए जाने के पीछे हमेशा से राजनीति होती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नया अर्थ और प्रासंगिकता दी है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख हों या फिर लालकृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, यह उन लोगों को सम्मानित करने की मोदी की राजनीति के स्पष्ट संकेत थे, जिन्हें कांग्रेस द्वारा नजर अंदाज और तिरस्कृत किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की मोदी की नवीनतम घोषणा से यह पता चलता है कि उनकी सरकार भारत की समकालीन राजनीति और अर्थव्यवस्था में इन तीनों हस्तियों की भूमिका को कितना महत्व देती है। इन्हें क्रमशः पहली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों, किसानों के हितों की वकालत करने वाले और बेहतर खाद्य उत्पादकता और सुरक्षा के लिए विज्ञान का उपयोग करने वाले चैंपियन के रूप में देखा जाता है। दिलचस्प यह है कि ये सभी 2024 के चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी के अभियान के पसंदीदा विषय हैं। दरअसल, महान कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन को यह पुरस्कार 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट को खत्म करने के लिए हरित क्रांति को लाने में उनकी बड़ी भूमिका को मान्यता देता है। यह स्वामीनाथन की रणनीति ही थी, जिसकी बदौलत भारत के कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से बतौर वैज्ञानिक उनके काम के परिणामस्वरूप पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को उच्च उपज की किस्म वाले बीज, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और उर्वरक उपलब्ध कराए गए।

वर्षों बाद, 2004 से 2006 के बीच राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. स्वामीनाथन ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), जिस पर किसान अपनी फसलें सरकार को बेचते हैं, वह औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 फीसदी ज्यादा होना चाहिए। डॉ. स्वामीनाथन के योगदान का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि आज ऐसा कोई दिन नहीं बीतता, जब किसानों के संघ कानूनी गारंटी के रूप में सभी उपज के लिए एमएसपी निर्धारित करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले को लागू करने की मांग न करते हों। यह महज संयोग तो नहीं हो सकता कि स्वामीनाथन को पुरस्कार तब दिया गया है, जब उपज की खरीद के लिए कानूनी गारंटी और बिजली के बिलों में संशोधन सहित अपनी लंबित मांगों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया हो।

दूसरी तरफ, चुनावी वर्ष में नरसिम्हा राव और चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार महज उनके योगदान को मान्यता नहीं है, बल्कि यह मतदाताओं की याद्दाश्त को ताजा करने का मोदी का तरीका है कि कैसे उन्होंने नेहरू-गांधी परिवार को चुनौती दी थी, जिससे सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के बारे में भाजपा का जो नैरेटिव रहा है, उसे ही मजबूती मिलती है।

इससे पहले वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। आडवाणी भाजपा के राम मंदिर आंदोलन का चेहरा थे, जिन्होंने 1992 के उन दृश्यों को देखा था, जब भीड़ द्वारा विवादित ढांचे को गिरा दिया गया था। कालांतर में इस आंदोलन ने एक लंबी कानूनी लड़ाई का रूप लिया, जिसकी परिणति सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के रूप में हुई, जिसने भव्य मंदिर खोलने का मार्ग प्रशस्त किया। कर्पूरी ठाकुर की भूमिका तो और भी महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ ओबीसी राजनीति का चेहरा नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के कट्टर आलोचक और बिहार में कांग्रेस विरोधी आंदोलन का गढ़ भी थे। बिहार के पहले ओबीसी मुख्यमंत्री के तौर पर ठाकुर राज्य में ओबीसी के लिए कोटा शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। नरसिम्हा राव नेहरू-गांधी परिवार से बाहर के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1991 में उदारीकरण की पहली लहर शुरू करने का राजनीतिक साहस दिखाया और 1996 तक बदलावों के लिए काम करते रहे, जब तक कि उनकी सरकार चुनाव हार नहीं गई। प्रधानमंत्री के रूप में अपने चुनौतीपूर्ण वर्षों के दौरान राव ने उस वक्त सोनिया गांधी के नजदीकी समझे जाने वाले शरद पवार और अर्जुन सिंह जैसे कांग्रेसी नेताओं की चुनौतियों का भी सामना किया। राव के कार्यकाल में गांधी परिवार और उनके समर्थकों के प्रभाव को कम किया गया, जिससे वह समकालीन कांग्रेस विरोधी नेताओं के लिए नायक बने। अयोध्या में विवादित ढांचे को बचाने में कथित विफलता के लिए सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने राव को दोषी ठहराया, पर एक सुधारवादी के रूप में उनका कौशल इन सब पर हावी रहा। 1996 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के जीतने में विफल रहने पर सोनिया गांधी और उनके वफादार नेताओं ने खुले तौर पर राव की विरासत को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण देवगौड़ा और गुजराल के नेतृत्व में एक गठबंधन हुआ, जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। हालांकि दिसंबर, 2004 में अपनी मृत्यु तक राव डॉ. मनमोहन सिंह जैसे अपने वफादार नेताओं के लिए आदरणीय और अविभाजित आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए राज्य के गौरवशाली पुत्र बने रहे। भाजपा का दावा है कि उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में रखने की अनुमति न देकर कांग्रेस नेतृत्व ने उनका अपमान किया। राव को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा तब हुई है, जब आगामी अप्रैल-मई में लोकसभा चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तेलंगाना में भी राव को भारत रत्न दिए जाने की मांग बीआरएस जैसी पार्टियां लंबे समय से करती आई हैं। चरण सिंह मामले में, जो इंदिरा गांधी द्वारा केवल 24 सप्ताह के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिए गए समर्थन के झांसे में आ गए थे, यह सम्मान जाट समुदाय में आज भी 'कुलक नेता' के रूप में प्रतिष्ठा के कारण उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। उनकी राजनीति को महत्व देने वालों के लिए वह 1970 के दशक में गैर-कांग्रेसवाद का एक प्रमुख चेहरा थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर किसानों के लिए उन्होंने जो किया, वह कृषि क्षेत्र के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके पोते और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी को एनडीए में शामिल करने के प्रयासों की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को देखा जा सकता है।

edit@amarujala.com

पाकिस्तान का चुनावी प्रहसन

पाकिस्तान के आम मतदाता पीटीआई उम्मीदवारों पर भरोसा जताते दिख रहे हैं, जो सैन्य प्रतिष्ठान के लिए चुनौती है। ऐसे में अगर सेना रातों-रात कोई खेल कर दे, तो आश्चर्य नहीं।

मारूफ रजा
रणनीतिक विश्लेषक

लगता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद भी राजनीतिक संकट जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अब तक घोषित नतीजों के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ समर्थित उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी दूसरे स्थान पर है, जबकि बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। एक से अधिक सीटों से चुनाव लड़ रहे नवाज शरीफ को नेशनल एसेंबली की 15 नंबर सीट से हार का सामना करना पड़ा है और वहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। नेशनल एसेंबली की 233 सीटों पर हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए 166 सीटों की जरूरत होगी। पाकिस्तान के लोग इस राजनीतिक प्रहसन को इलेक्शन (चुनाव) के बजाय सेलेक्शन (चयन) बता रहे हैं, जबकि मानवाधिकार पर्यवेक्षकों ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि चुनाव न तो स्वतंत्र था और न ही निष्पक्ष। अमेरिका स्थित गैलप पोलिंग कंपनी ने पाया कि पाकिस्तान के लोग आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से हतोत्साहित हैं, जो उनके मुल्क की स्थिरता को खतरे में डालती हैं, और मतदान से पहले ही असंतोष रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। गैलप के सर्वेक्षण में कहा गया कि पाकिस्तान का राजनीतिक माहौल उतना ही निराशाजनक है, जितना आर्थिक माहौल। दस में से सात पाकिस्तानियों को इस चुनाव की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। और हाल ही में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमलों और पीओके एवं गिलगित बाल्टिस्तान में बढ़ते असंतोष ने सैन्य प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया है।

असंख्य खतरों से निपटने के लिए पाकिस्तान ने 6,50,000 से अधिक सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को हजारों मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए तैनात किया। और यह सुनिश्चित किया कि सैन्य प्रतिष्ठान अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। मतदान के दिन देश भर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बाधित रहीं, जिसके खिलाफ विपक्षी दलों एवं लोगों में भारी नाराजगी दिखी। पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान ने इमरान खान की किस्मत पर ताला जड़ दिया है।

लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के आम मतदाता पीटीआई उम्मीदवारों पर इस चुनाव में भरोसा जताते हुए दिख रहे हैं, वह पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के लिए एक नई चुनौती है। सेना इमरान खान को समर्थन देगी, इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। इमरान खान ने चुनाव नतीजों में धांधली का आरोप भी लगाया है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान रातों-रात कोई खेल कर दे, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस बात की पूरी संभावना है कि मियां नवाज शरीफ सेना द्वारा 'चयनित' प्रधानमंत्री बन सकते हैं।

पाकिस्तान के चुनाव में सभी दावेदारों का कहना है कि वे मुल्क को उस गंदगी से बाहर निकालेंगे, जो सेना के लालच और पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार ने पैदा की है। लेकिन क्या वे ऐसा कर सकते हैं? नवाज शरीफ ने चुनाव में चाहे जो भी वादे किए हों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं ला सकते हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने का भी वादा किया है, लेकिन तुरंत उनसे कुछ खास उम्मीद नहीं की जा सकती है।

पाकिस्तानी सेना चाहे जिसे भी अपनी कठपुतली के रूप में अगला प्रधानमंत्री चयनित करे, वहां सामाजिक और जातीय विभाजन इतना गहरा गया है कि कोई भी राजनीतिक मैच फिक्सिंग इसे ठीक करने में सक्षम नहीं होगी। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्ज और राहत पैकेज पर टिकी अर्थव्यवस्था के साथ आतंकवाद को अपनी नीति का साधन बनाने से आपदा ही आएगी।

दूसरा पहलू

बीते करीब तीन दशक में दसियों लाख अमेरिकी अश्वेतों को मजबूरी में दक्षिण की ओर जाकर बसना पड़ा है।

क्यों विस्थापित हो रहे अमेरिका के अश्वेत?

डेट्रॉयट में एमा लॉकरिज के पड़ोस में और आसपास प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा था कि खुद एमा को ही घर के अंदर सर्जिकल मास्क लगाए रहना पड़ता था। पास की रिफाइनरियों और फैक्टरियों से इतना धुआं निकलता था कि उसकी खिड़की से बाहर आकाश हमेशा काला दिखता था। 'धुआं और प्रदूषण इतना ज्यादा था कि मैं रात को सो नहीं पाती थी', एमा ने पिछले साल मुझसे कहा था। एमा के पड़ोस में भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लोग मजबूरी में ही वहां रह रहे थे। वर्ष 2021 में एमा ने भी विवश होकर डेट्रॉयट छोड़कर मेम्फिस का रुख किया, हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि वहां भी प्रदूषण कोई कम नहीं है। दक्षिण की तरफ विस्थापन करने वाली एमा अकेली नहीं हैं। बीते करीब तीन दशक में दसियों लाख अमेरिकी अश्वेतों को मजबूरी में दक्षिण की ओर जाकर बसना पड़ा है। यह सीधे-सीधे रिवर्स माइग्रेशन है; असंख्य अश्वेत लोग अब उन्हीं इलाकों में वापस लौट रहे हैं, जहां से उनके पूर्वज 1910 से 1970 के बीच बेहतर आर्थिक संभावनाओं के कारण बाहर निकले थे। वर्ष 2015 से 2020 के बीच अश्वेतों ने दक्षिण की जिन छह जगहों को बसने के लिए चुना, उनमें जॉर्जिया, टेक्सास और फ्लोरिडा प्रमुख रहे।

एडम मेहोनी

यह सीधे-सीधे रिवर्स माइग्रेशन है; असंख्य अश्वेत लोग अब उन्हीं इलाकों में वापस लौट रहे हैं, जहां से उनके पूर्वज 1910 से 1970 के बीच बेहतर आर्थिक संभावनाओं के कारण बाहर निकले थे।

कई विश्लेषकों का कहना है कि आर्थिक मुश्किलों और करों के बोझ के कारण अश्वेत समुदाय के लोगों का दक्षिण की ओर जाने का सिलसिला जारी है।

अमेरिका में अश्वेतों के इस आंतरिक प्रवासन का अध्ययन करने के लिए मैं अगस्त, 2022 से ही अश्वेत समुदाय के लोगों से बातचीत करता रहा हूं। मेरी उत्सुकता का एक कारण यह भी है कि इस विस्थापन का अमेरिका के दक्षिण में क्या और कितना असर पड़ रहा है। जाहिर है, इतनी बड़ी संख्या में विस्थापन का कोई एक कारण नहीं हो सकता। कई विश्लेषकों का कहना है कि आर्थिक मुश्किलों और करों के बोझ के कारण अश्वेत समुदाय के लोगों का दक्षिण की ओर जाने का सिलसिला जारी है। मेरा मानना है कि प्रदूषण भी विस्थापन का एक कारण है।

चूंकि जलवायु परिवर्तन का असर दक्षिण में भी है, लिहाजा विस्थापित अश्वेतों को वहां भी प्रदूषण के साथ-साथ पर्यावरणीय बदलावों का सामना करना पड़ेगा। पर यह स्थिति सिर्फ अश्वेत समुदाय के लिए नहीं, बल्कि चुने गए अधिकारियों और स्थानीय नेतृत्व के लिए भी चिंता का कारण होनी चाहिए। लोकतांत्रिक अमेरिका में आर्थिक नीति अश्वेत समुदाय के लिए लाभदायक और समावेशी तो होनी ही चाहिए, प्रदूषण रोकने और कम करने के लिए भी तमाम कदम उठाए जाने चाहिए। तभी अश्वेत समुदाय को मजबूरन विस्थापित होने से रोका जा सकेगा।

©The New York Times 2024

आंकड़े

बढ़ते घरेलू हवाई यात्री

देश भर में हवाई जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है। 2023 में अब तक सबसे ज्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है।

नोट : आंकड़े करोड़ में हैं।

स्रोत : Directorate General of Civil Aviation (DGCA)

भगवद्भक्तों की कोई जाति नहीं होती। जो भी एक साथ संकीर्तन करते हैं, वे सब एकाकार होकर एक जाति के हो जाते हैं।

भक्त की जाति नहीं होती

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

भक्त नरसी मेहता जूनागढ़ (सौराष्ट्र) में गृहस्थ जीवन बिताते हुए भगवान की पूजा, उपासना तथा रोगियों की सेवा में लगे रहते थे। वह अपने रचे पदों को तन्मय होकर गाते थे और श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठते थे।

एक दिन दलित समुदाय के एक भक्त ने उनसे पूछा, 'क्या आप मेरे घर पधार कर संकीर्तन कर उसे पवित्र कर सकते हैं?' मेहता जी ने कहा, 'कीर्तन क्यों नहीं किया जा सकता? तुम तैयारी करो, मैं समय पर पहुंचकर तुम्हारे परिजनों के बीच कीर्तन करूंगा।'

नरसी मेहता उसके घर पहुंचे। तन्मय होकर भगवान का संकीर्तन किया। प्रसाद ग्रहण किया। उनकी जाति के कुछ रूढ़िवादी सवर्णों को जब यह पता चला, तो उन्होंने पंचायत कर नरसी मेहता को अंत्यज (दलित) के घर कीर्तन करने के आरोप में जाति से बहिष्कृत कर दिया।

नरसी मेहता ने सवर्ण जाति के मुखिया से विनम्रता से कहा, 'भगवद्भक्तों की कोई जाति नहीं होती। जो भी एक साथ संकीर्तन करते हैं, वे सब एकाकार होकर एक जाति के हो जाते हैं। आप लोगों ने मुझे केवल एक जाति के दायरे से निकालकर सचमुच मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं आप सबका आभारी हूं।'

मुखिया सारंगधर भक्त नरसी का मुंह देखता रह गया।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 6 जनवरी, 1955

ब्रिटेन भारत के विकास में हर तरह की मदद देने को तैयार

ब्रिटेन भारत की मदद को तैयार

नई दिल्ली, 6 जनवरी। ब्रिटेन के व्यापार विभाग के राज्य मंत्री श्री ए० आर० डब्लू लो ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि ब्रिटेन भारत के औद्योगिक विकास में उसे हर तरह की मदद देने के लिये तैयार है। उन्होंने इस्पात के उस कारखाने की भी चर्चा की जो ब्रिटिश उद्योग-

ब्रिटेन के व्यापार विभाग के राज्य मंत्री ए आर डब्ल्यू लो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रिटेन भारत के औद्योगिक विकास में हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने इस्पात के उस कारखाने की भी चर्चा की, जो ब्रिटिश उद्योगपतियों की मदद से बनाया जाना है।

हिमालय में कम बर्फबारी के मायने

इस बार पहाड़ों पर बर्फ न गिरने से हिमालयी राज्यों समेत देश भर में संकट खड़ा हो गया है। इसके लिए हमें स्थानीय मूल कारकों पर ध्यान देना होगा।

पंकज चतुर्वेदी

पर्यावरण

क्या हिमालय की गोद में बसे भारत के कई राज्य, नेपाल और पाकिस्तान के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में देर से हुई बर्फबारी महज एक असामान्य घटना है या फिर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का संकेत? यह बात गौर करने की है कि बीते कुछ वर्षों में हिमालय लगातार असामान्य और चरम मौसम की चपेट में है, और इस बार बरसात ने हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक जबर्दस्त कहर ढाया था। लेकिन इस बार लगातार 45 दिन तक पहाड़ों पर बर्फ न गिरने से हिमालयी राज्य ही नहीं, शेष भारत के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। जान लें, देर से हुई बर्फबारी से राहत तो है, पर इससे उपजे खतरे भी हैं।

कश्मीर के बाशिंदों के लिए जीवकोपार्जन का मूल आधार है-जाड़े का मौसम। यहां जाड़े के कुल 70 दिन गिने जाते हैं। सत्तर दिन की बर्फबारी 15 दिन में सिमटने से दिसंबर और जनवरी में हुई लगभग 80-90 फीसदी कम बर्फबारी की भरपाई तो हो नहीं सकती। उसके बाद गर्मी शुरू हो जाने से जो थोड़ी-सी बर्फ पहाड़ों पर आई है, वह जल्दी ही पिघल जाएगी। अर्थात आने वाले दिनों में एक तो ग्लेशियर पर निर्भर नदियों में बाढ़ आ सकती है और फिर अप्रैल में गर्मी आने पर वहां पानी का अकाल हो सकता है।

देश में हिमालयी क्षेत्र का फैलाव 13 राज्यों व कई केंद्रशासित प्रदेशों में है, जो करीब 2,500 किलोमीटर में फैले हुए हैं। भारत के मुकुट कहे जाने वाले हिमाच्छादित पर्वतमाला की गोदी में कोई पांच करोड़ लोग सदियों से रह रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की मार से सर्वाधिक प्रभावित उत्तराखंड के पहाड़ जैसे अब अपना संयम खो रहे हैं। देश को सदानीरा गंगा-यमुना जैसी नदियां देने वाले पहाड़ के करीब 12 हजार प्राकृतिक स्रोत या तो सूख चुके हैं या फिर सूखने के कगार पर हैं। इस सर्दी में हिमालय, हिंदू-कुश और काराकोरम में बर्फबारी की असामान्य अनुपस्थिति के चलते गर्म तापमान रहा है। जलवायु संकट के प्रतीक ये बदलाव पर्वतीय समुदायों और हिंदू-कुश हिमालयी क्षेत्र में जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। यह समझना होगा कि सर्दियों में कम बर्फबारी का कारण अल नीनो नहीं है। अल नीनो के कारण केवल गर्मी और मानसून की बारिश प्रभावित होती है।

गौरतलब है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हैं। वे अपना निर्वाह खेती और पशुधन पालन से करते हैं। लगभग बर्फ रहित या देर से सर्दी का प्रभाव उन लोगों के लिए विनाशकारी हो सकता है। पूरे हिमालयी क्षेत्र में कम बर्फबारी और अनियमित बारिश से पानी और कृषि वानिकी सहित प्रतिकूल पारिस्थितिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। अगर तापमान जल्द ही बढ़ जाता है, तो देर से होने वाली बर्फबारी और भी अधिक त्रासद होगी। गर्मी से यदि ग्लेशियर अधिक पिघले, तो आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों में स्थापित सैंकड़ों मेगा वाट की जल विद्युत परियोजनाओं पर भी संकट आ सकता है। लंबे समय तक सूखे के कारण झेलम और अन्य नदियों का जल स्तर अभी से नकारात्मक सीमा में है। देश की संपन्न अर्थव्यवस्था का आधार खेती है, जो बगैर सिंचाई के हो नहीं सकती। इसके लिए अनिवार्य है कि नदियों में जल-धारा अविरल रहे, लेकिन नदियों में जल लाने की जिम्मेदारी तो उन बर्फ के पहाड़ों की है, जो गर्मी होने पर धीरे-धीरे पिघलकर देश को पानीदार बनाते हैं। साफ है कि आने वाले दिनों में न केवल कश्मीर या हिमाचल, बल्कि पूरे देश में जल संकट खड़ा होगा।

ऐसे में, सवाल यह उठता है कि इस अनियमित मौसम से कैसे बचा जाए? ग्लोबल वार्मिंग या अल नीनो को दोष देने से पहले हमें ऐसे स्थानीय कारकों पर विचार करना होगा, जिससे प्रकृति कूपित है। जून, 2022 में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट 'एनवायरनमेंटल असेसमेंट ऑफ टूरिज्म इन द इंडियन हिमालयन रीजन' में कड़े शब्दों में कहा गया था कि हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते पर्यटन के चलते हिल स्टेशनों पर दबाव बढ़ रहा है। साथ ही पर्यटन के लिए जिस तरह से इस क्षेत्र में भूमि उपयोग में बदलाव आ रहा है, वह अपने-आप में एक बड़ी समस्या है। जंगलों का बढ़ता विनाश भी इस क्षेत्र के इकोसिस्टम पर व्यापक असर डाल रहा है। इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के वाहनों और इसके लिए बन रही सड़कों के कारण वन्यजीवों के आवास नष्ट होने और जैव विविधता पर विपरीत असर पड़ने की बात भी कही गई थी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 16 अंक 305

संतुलित दृष्टिकोण

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के वर्ष 2020-21 और 2021-22 के आंकड़े जारी कर दिए। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से मची उथल पुथल से जूझ रही थी। बहरहाल, परिणाम दिखाते हैं कि देश का विनिर्माण क्षेत्र कच्चे माल के इस्तेमाल, उत्पादन और मुनाफे के मामले में मजबूत है। एएसआई पूरे देश में विस्तारित है और यह औद्योगिक आंकड़ों का सबसे प्रमुख स्रोत है। यह 10 या अधिक कर्मचारियों वाली और बिजली का इस्तेमाल करने वाली तथा बिना बिजली की खपत वाली लेकिन 20 से अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों को गणना में लेती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 17 फीसदी है। समीक्षा अवधि में जहां देश के औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहा, वहीं इसका अपेक्षाकृत छोटा पैमाना और सघनता चिंता का विषय है।

विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्यवर्द्धन में वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 में मौजूदा दरों पर क्रमशः 8.8 फीसदी और 26.6 फीसदी की वृद्धि हुई। उत्पादन में कमी के बावजूद 2020-21 में सकल मूल्यवर्धन में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली क्योंकि कच्चे माल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई थी। यह बात ध्यान देने लायक है कि उत्पादन में केवल वित्त वर्ष 21 में ही गिरावट नहीं आई बल्कि उसके पिछले वर्ष भी इसमें गिरावट आई थी जबकि वित्त वर्ष 22 में इसने वापसी की। रोजगार के संदर्भ में बात की जाए तो अनुमान के मुताबिक ही वित्त वर्ष 21 में इसमें मामूली कमी आई। परंतु अगले वर्ष इसकी अच्छे से भरपाई हो गई और रोजगार में सालाना आधार पर सात फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इस क्षेत्र में प्रति कर्मचारी औसत क्षतिपूर्ति में भी सर्वेक्षण में शामिल दो वर्षों के दौरान इजाफा देखने को मिला। इसके अलावा महामारी ने नियोजित पूंजी को भी प्रभावित नहीं किया। स्थायी पूंजी और निवेश की गई पूंजी दोनों में संदर्भ अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली।

इन सब बातों के बीच विनिर्माण गतिविधि भौगोलिक रूप से कुछ खास इलाकों तथा चुनिंदा उत्पादों में सिमटी हुई है।

एएसआई के परिणामों ने दिखाया कि केवल पांच राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 21 और 22 में विनिर्माण के कुल मूल्यवर्द्धन में 50 फीसदी से अधिक योगदान किया। इसके साथ ही बुनियादी धातु, कोयला और रिफाइंड पेट्रोलियम, फार्मास्युटिकल उत्पाद, वाहन, खाद्य और रासायनिक उत्पाद उद्योगों ने मिलाकर इस क्षेत्र के कुल मूल्यवर्द्धन में 56 फीसदी का योगदान किया। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के बावजूद वित्त वर्ष 22 में विनिर्माण क्षेत्र में 1.7 करोड़ से कुछ अधिक लोग ही रोजगारशुदा हैं।

यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमियों में से एक है। हम विनिर्माण क्षेत्र में इतने अधिक रोजगार नहीं तैयार कर सके हैं कि लोगों को कृषि कार्यों से बाहर निकाल सकें क्योंकि वहां उत्पादकता बहुत कम है। सरकार ने अपनी ओर से हस्तक्षेप किया है और निवेश बढ़ाने के लिए कई क्षेत्रों में कम कॉर्पोरेशन कर, सिंगल विंडो मंजूरी और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना आदि की पेशकश की है। यह उम्मीद भी की जा रही है कि वैश्विक कंपनियों द्वारा चीन से दूरी बनाने का नतीजा भारत में अधिक निवेश के रूप में सामने आएगा। यद्यपि अब तक इस दिशा में सीमित सफलता मिली है। भारत को लगातार निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता है। सरकार के सामने न केवल उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए उच्च निवेश की आवश्यकता है बल्कि उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निवेश गिनेचुने राज्यों तक सीमित नहीं रहे। औद्योगिक उत्पादन और रोजगार के क्षेत्र में एकतरफा झुकाव वाली वृद्धि संघीय व्यवस्था में तनाव पैदा कर सकती है। अलग-अलग रूप में यह नजर भी आने लगा है।

अजय मोहंती

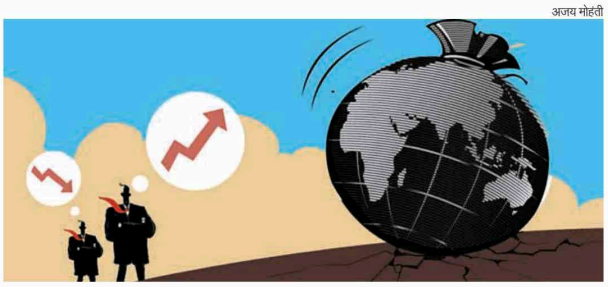

कहीं अत्यधिक आशावादी तो नहीं हैं बाजार?

वैश्विक स्तर पर विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वित्तीय बाजार लगातार आशावादी बने हुए हैं। इन बाजारों के हालात तथा भारत पर इसके असर के बारे में बता रहे हैं अजय शाह

फरवरी 2022 में अनिश्चितता तेजी से बढ़ी। फरवरी 2023 में इस समाचार पत्र में प्रकाशित मेरे स्तंभ का शीर्षक कह रहा था कि अनिश्चितता में निश्चित रूप से कमी आ रही है। उसके बाद वर्ष के दौरान कई सकारात्मक घटनाएं घटीं और शायद यही कारण है कि वित्तीय बाजार अति आशावाद के शिकार हैं। गत वर्ष का बड़ा सवाल यह था कि कोविड के बाद विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से गति कैसे प्रदान की जाए? बड़े पैमाने पर दिए जाने वाले मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी। यह 1970 के दशक के मुद्रास्फीति संकट की तरह नहीं था जब नीतिगत रणनीति को लेकर अनुमान लगाना सहज था क्योंकि मुद्रास्फीति को लक्षित किया जा रहा था।

परंतु सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या रोजगार को लेकर होने वाले नुकसान के बारे में बहुत निराशा थी जो मुद्रास्फीति को कम करने में मददगार होगी। इस दौरान चीजें बेहतर ढंग से घटित हुईं। विकसित देशों की मुद्रास्फीति बिना बेरोजगारी या जीडीपी वृद्धि पर असर डाले कम हुई। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी है जहां अमेरिका में वृद्धि मजबूत बनी हुई है, चीन में वृद्धि का स्तर कम है और यूरोप तथा जापान में वृद्धि कमजोर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया है कि 2024 में अमेरिका का वास्तविक जीडीपी 2.1 फीसदी तथा जापान और यूरो क्षेत्र का 0.9 फीसदी बढ़ेगा। विकसित बाजारों में ब्याज दरों में पहली कटौती प्रतीकात्मक होगी जो बताएगी कि कोविड के बाद का मुद्रास्फीति का दौर बीत रहा है। वित्तीय बाजार 2024 में ऐसी घटनाओं को लेकर आशावादी हैं। वीआईएक्स यानी वॉलैटिलिटी इंडेक्स और मूव (मेरिल लिंच ऑप्शन वॉलेटिलिटी एस्टीमेट इंडेक्स) के रूप में अनिश्चितता को मापने वाले दो सूचकांक हैं। बीते वर्षों के दौरान वीआईएक्स में 29 फीसदी की गिरावट आई जबकि मूव अपरिवर्तित रहा। यदि विकसित देशों में 2024 में ब्याज दरों में कटौती होती है तो भारत में पूंजी की आवक का नया दौर देखने को मिल सकता है। यह विश्व अर्थव्यवस्था में एक अहम मोड़ है जहां वर्तमान और भविष्य का अनुमान लगाते हुए भारत के लिए निहितार्थों का आकलन किया जा सकता है।

विकसित देशों में मुद्रास्फीति में गिरावट क्यों आई? महामारी के कारण आपूर्ति में आई बाधा दूर हो गई। इसके साथ ही रूस ने ऊर्जा के मामले में यूरोप को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया लेकिन वह इससे सफलतापूर्वक निपटने में कामयाब रहा। अमेरिका अब दुनिया का सबसे बड़ा गैस निर्यातक है। कोविड के अंतिम दिनों में अस्थायी मुद्रास्फीति को लेकर एक आशावादी व्याख्या यह थी कि कंपनियों को कुछ समय तक अच्छा मार्जिन प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे उत्पादन को दोबारा शुरू करने की तयशुदा लागत चुका सकें।

अमेरिका का प्रदर्शन इतना अच्छा क्यों है? आंशिक तौर पर ऐसा महामारी से उबरने के क्रम में हुआ जहां अच्छी किस्मत भी साथ थी। अमेरिकी श्रम बाजार अन्य विकसित बाजारों की तुलना में अधिक लचीले हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन की टीम पिछली सरकार की तरह लोकलुभावन कदम उठाने के बजाय गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था वाली टीम है। उसके बेहतर सोच और नीतिगत निर्णयों ने भी सकारात्मक अंतर पैदा किया।

यूरोप और अमेरिका में स्थित रक्षा क्षेत्र का औद्योगिक आधार यूक्रेन युद्ध के बाद बढ़ाया जा रहा है। रक्षा व्यय का डॉलर मूल्य अभी भी काफी कम है और खरीद प्रक्रिया अक्सर विनिर्माण प्रक्रियाओं में नए निवेश को गति दे रही हैं जो अन्यथा कमजोर पड़ चुकी थीं। एक डॉलर की प्रतीत होने वाली खरीद भी दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला में निवेश को कई स्तरों पर बढ़ावा दे रही है।

वर्ष 2024 के लिए पांच अहम चुनौतियां इस प्रकार हैं:

1. कई देशों में 2024 में चुनाव होने हैं और कई लोकलुभावन बातों वाले नेता जीत सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में देखें तो विक्टर ओर्बन की अवज्ञा आंशिक तौर पर उनके इस दांव पर आधारित हो सकती है कि एक साल के भीतर यूरोपीय संघ में उनके जैसे कई लोकलुभावन नेता उत्पन्न हो जाएंगे। चुनावी साल में कई देशों की सरकारें अलग तरह से व्यवहार करेंगी। अगर डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो दुनिया भर में उथलपुथल मच जाएगी और यूक्रेन और जलवायु परिवर्तन जैसी दिक्कतें बढ़ेंगी।

2. यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया को मुश्किल में डाला और यह अब भी जारी है। अगर कोई देश पड़ोसी मुल्क पर हमला कर देगा तो कोई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था नहीं बचेगी। यह युद्ध कई स्तरों पर अस्थिरता बढ़ा रहा है। यूक्रेन युद्ध ने हालात नहीं बदले होते तो ईरान भी पश्चिम एशिया में इतना आक्रामक नहीं होता।

3. तीसरा वैश्वीकरण आकार ले रहा है। यह वह चरण है जहां सर्वाधिक आर्थिक प्रभुत्व उन देशों के इर्दगिर्द होता है जो कम विदेश नीति और सैन्य संरेखण वाले हों। इससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बेहतरी आती है लेकिन इसकी कीमत आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर चुकानी होती है।

4. नकदी की उच्च उपलब्धता दुर्घटनाओं की संभावना पैदा करती है। अब तक की उल्लेखनीय बात यह है कि उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंकों द्वारा इतना धन जुटाने के बीच गलतियां बहुत कम हुईं। इसके बावजूद हम पूरी तरह निश्चिंत होने की स्थिति में नहीं हैं।

5. आखिर में जैसा कि हम 2020 के बाद से ही जोर दे रहे हैं, हम नए परिदृश्य से मुखातिब हैं। वर्तमान मॉडल और सिद्धांत सामान्य समय को ध्यान में रखकर बने हैं। ऐसे में गलतियां होना संभव है।

वित्तीय बाजारों के एसऐंडपी 500 और वीआईएक्स के मूल्यांकन में वित्तीय बाजारों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। भारत की बात करें तो भारतीय निर्यात का सबसे बेहतर माप सोने और पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर अन्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना है। इस आधार पर फरवरी 2022 के बाद से निर्यात स्थिर रहा है। फरवरी 2022 के बाद से विकसित बाजारों का अस्वाभाविक रूप से बेहतर प्रदर्शन भारतीय निर्यात की उछाल में शामिल नहीं है। अगर विकसित बाजारों में तेजी जारी रही तो क्या भारतीय निर्यात में सुधार होगा? यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय निर्यात को नुकसान होगा।

गाजा में चल रही लड़ाई विश्वस्तर पर कोई बहुत गहन युद्ध नहीं है लेकिन यह भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि स्वेज नहर के रास्ते मालवहन मुश्किल हो गया है। भारत से यूरोप और अमेरिका के पूर्वी द्वीप को जाने का यह प्रमुख रास्ता है जो फिलहाल बाधित है और केप ऑफ गुड होप के जरिये दूसरे मार्ग से माल ढोने पर लागत बढ़ गई है। बंबई और कराची दुनिया के दो बंदरगाह हैं जहां स्वेज नहर अधिक मायने रखती है।

भारत में निवेश की कमजोरी के कारण चालू खाते का घाटा अधिक नहीं है। ऐसे में वैश्विक वित्तीय हालात में बदलाव रुपये के लिए हालात को मुश्किल नहीं बनाएगा। हालांकि कई परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है क्योंकि वीआईएक्स और भारतीय परिसंपत्ति के मूल्यांकन में संबंध है।

(लेखक एक्सकेडीआर फोरम में शोधकर्ता हैं)

मुद्रास्फीति नियंत्रण का वादा पूरा करेंगे दास!

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तीन दिन की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के आखिर में एक बार फिर महंगाई को नियंत्रित करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को टिकाऊ आधार पर 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए मौद्रिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि कीमतें बढ़ें लेकिन उनकी बढ़ने की दर धीमी हो।

एमपीसी ने सख्त नीति अपनाने और आर्थिक प्रोत्साहन वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लेते हुए मई 2020 और फरवरी 2023 के बीच नीतिगत दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि के साथ इसे 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत करने का फैसला किया ताकि मुद्रास्फीति से जुड़ी उम्मीदों को आधार मिले।

गुरुवार की सुबह अपने 39 मिनट के वक्तव्य को करीब एक सांस में पढ़ते हुए दास ने करीब आधा घंटे बाद पहली बार पानी का घूंट पिया। ऐसा लगता है कि दास तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक वह महंगाई की दर 4 प्रतिशत के लक्षित स्तर तक लाने का अपना वादा पूरा नहीं कर लेते हैं।

निश्चित रूप से 2022 की गर्मी के मौसम के बाद से मौद्रिक नीति के तहत वृद्धि की तुलना में मुद्रास्फीति को प्राथमिकता दी जा रही है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा, 'काम अभी पूरा नहीं हुआ है और हमें नई नकदी आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियों को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए क्योंकि इससे अब तक की हुई प्रगति नाकाम हो सकती है।'

अब तक लगातार छठी एमपीसी बैठक में भी रीपो दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 6.5 प्रतिशत के स्तर पर है और आरबीआई का रुख आर्थिक प्रोत्साहन को खत्म करना है। हालांकि मौद्रिक नीति की कहानी में एक नया मोड़ आया है। आरबीआई ने अपने रुख को नकदी से अलग करने की कोशिश की है। हालांकि यह रुख केंद्रीय बैंक के नकदी से जुड़े रुख को प्रतिबिंबित नहीं करता है बल्कि यह नीतिगत दर के स्वाभाविक परिणाम को दर्शाता है।

एमपीसी के बयान में कहा गया है कि नीतिगत रुख, ब्याज दर के लिहाज से है जो मौजूदा ढांचे में मौद्रिक नीति का प्रमुख जरिया है। ऐसे में आर्थिक प्रोत्साहन वापस लिए जाने के कदम को मुद्रास्फीति के लक्षित 4 प्रतिशत के स्तर से ऊपर चले जाने और आरबीआई द्वारा टिकाऊ आधार पर इस लक्ष्य के स्तर पर वापस लाने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जहां तक नकदी से जुड़ी परिस्थितियों का संबंध है, यह कई बाहरी कारकों से (सरकार की नकदी आरबीआई के पास है) प्रेरित होता है।

सरकार ने खर्च करना शुरू कर दिया है जिससे अब तंत्र में नकदी बढ़ेगी। आरबीआई भी नकदी प्रबंधन में चुस्त और लचीला बना रहेगा। दास ने यह आश्वासन भी दिया है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक बाजार की ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए सभी तरह के उपाय करेगा ताकि अस्थायी और दीर्घकालिक नकदी का संतुलन बनाया जा सके। इसका अर्थ यह है कि आरबीआई रीपो दर पर नकदी का संचार करता रहेगा और अस्थायी उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए परिवर्तनीय रिवर्स दर नीलामी के माध्यम से इसे वापस ले लेगा।

संयोग की बात है कि सरकारी नकदी के समायोजन के बाद, बैंकिंग तंत्र में संभावित नकदी अब भी अधिशेष के स्तर में है। यह बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) या जमा राशि के उस हिस्से में कटौती की किसी भी संभावना को समाप्त कर देता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को नकदी कम करने के लिए (वर्तमान में 4 प्रतिशत) केंद्रीय बैंक के पास रखने की आवश्यकता होती है।

चालू वर्ष के लिए आरबीआई के मुद्रास्फीति अनुमान में कोई बदलाव नहीं है। यह 5.4 प्रतिशत के स्तर पर है। अगले साल सामान्य मॉनसून रहने की संभावना के चलते वित्त वर्ष 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) से जुड़ी मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत होगी जो पहली तिमाही के लिए 5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही के लिए 4 प्रतिशत, तीसरी के लिए 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 4.7 प्रतिशत होगी।

जब बात वृद्धि की आती है तब आरबीआई काफी उत्साहित नजर आ रहा है। वित्त वर्ष 2025 के लिए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का अनुमान 7 प्रतिशत है, जो लगातार चौथे वर्ष 7 प्रतिशत (या अधिक) वृद्धि के संकेत देता है। चालू वर्ष के लिए अनुमान 7.3 प्रतिशत है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सांकेतिक जीडीपी वृद्धि अनुमान 10.5 प्रतिशत के स्तर पर आंका है।

आरबीआई की नीति पर विश्लेषकों की राय बंटी हुई। क्या इस नीति का मुख्य उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित करना है, भले ही इसके लिए आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कम क्यों न करनी पड़े या फिर इसकी प्राथमिकता आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है?

दास ने बेहद सावधानी से आगे की कोई भविष्यवाणी करने से परहेज किया है। मैं इसे उनकी 'ठहरकर इंतजार करने' की नीति कहूंगा। दरअसल आरबीआई पर बहुत कुछ करने का दबाव नहीं था क्योंकि भारत अधिकांश वृहद आर्थिक मानकों के लिहाज से अच्छी स्थिति में है। देश का ऋण और जीडीपी अनुपात ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है। इसके अलावा चालू खाता घाटा भी वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में जीडीपी के एक प्रतिशत से कम हो गया है जो एक साल पहले 3.8 प्रतिशत था। स्थानीय मुद्रा, उभरती अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक की कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में स्थिर है। इसके अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अब तक इस वर्ष 32.4 अरब डॉलर रहा है जबकि पिछले साल करीब 6.7 अरब डॉलर की पूंजी निकल गई। इसके अलावा मुद्रास्फीति में भी गिरावट के रुझान है लेकिन वृद्धि मजबूत बनी हुई है।

अब सवाल यह है कि हम अगली दर कटौती कब देखेंगे? आरबीआई इसको लेकर किसी हड़बड़ी में नहीं होगा, खासतौर पर तब जब यह वृद्धि की संभावनाओं को लेकर आश्वस्त न हो। मौद्रिक नीति की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में दास ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे दुनिया के कई हिस्सों में दर कटौती के संदर्भ में बाजार की भूमिका है। हमें मौजूदा चक्र में अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा पहली दर कटौती का इंतजार करना होगा। यदि भू-राजनीतिक परिदृश्य में कोई आश्चर्यजनक बदलाव नहीं आता है और मॉनसून सामान्य रहता है तब हम साल की दूसरी छमाही में यह कटौती देख सकते हैं।

आपका पक्ष

विश्वविद्यालय ही शोध के स्तंभ

लेख 'शोध एवं विकास व्यय में इजाफा' देश में शोध एवं नवोन्मेष पर गंभीर चर्चा करता है। हालांकि बड़ी तकनीकी कंपनियां कॉरपोरेट स्तर पर अपने संसाधनों से शोध एवं नवोन्मेष करती हैं जिसका प्रभाव उनके उत्पादों और गुणवत्ता में स्पष्ट दिखाई देता है। सरकार ने अंतरिम बजट में शोध एवं नवोन्मेष के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है जबकि स्कूली शिक्षा के लिए 73,480 करोड़ रुपये रखे हैं जो पिछले बजटों की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। शोध और नवोन्मेष की व्यापकता के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों को ही शोध का केंद्र रखा जाए। उच्च कोटि के आईआईटी और एम्स जैसे संस्थानों में शिक्षा, विज्ञान, मेडिकल एवं औद्योगिक विकास और आवश्यकताओं और सामाजिक हित के लिए उपयोगी शोध किए जा सकते हैं जिनमें शोध के निमित्त आवंटित वित्त पोषण का उपयोग हो सकता है और छात्रों के लिए भी शोध में एक आकर्षक और सम्मानजनक भविष्य की संभावनाएं बन सकती हैं। यहां यह भी समझना आवश्यक है कि जब सरकार शोध और नवोन्मेष के प्रति गंभीर है तो प्रतिभा पलायन रोकना भी जरूरी है और अपने होनहार शोधकर्ताओं को स्वदेश वापस बुलाने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए कोई लंबे चौड़े कार्यक्रम या योजनाओं की जरूरत नहीं बल्कि कॉरपोरेट, विश्वविद्यालय, सरकारी और स्वायत्त संस्थाएं शोध के क्षेत्र में वेतन में सम्मानजनक वृद्धि करें। हमारे देश में शोध एक करियर के रूप में स्थापित नहीं है और राजनीतिक पटल पर शिक्षा कोई गंभीर विषय या एजेंडा नहीं है। जैसे विकास और स्वच्छता आंदोलन के रूप में स्थापित हो चुके हैं, वैसे ही शिक्षा भी एक आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित हो जिससे भविष्य की युवा पीढ़ी विकसित और समृद्ध भारत की वाहक बने।

विनोद जौहरी, दिल्ली

फरीदाबाद में आयोजित 37वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले में शुक्रवार को एक कॉलेज के छात्र-छात्राएं

कोचिंग संस्थानों में कम उम्र के बच्चों का प्रवेश बंद

अब कम उम्र के बच्चों का प्रवेश कोचिंग संस्थानों में नहीं हो सकेगा। अच्छे नंबरों या फिर अच्छी रैंकिंग की गारंटी देने वाले संस्थान हमेशा ही कम उम्र के बच्चों को अपने कोचिंग संस्थानों में प्रवेश देकर बड़ी-बड़ी कक्षाएं चलाने लगते हैं जबकि यह बेहद जरूरी है कि बड़ी कक्षाओं एवं 16 साल से अधिक उम्र के बच्चों यानी नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं या स्नातक के लिए कोचिंग हो। इसी तरह से कॉलेज के छात्र अगर कोचिंग के लिए आते हैं तो यह भी उनकी समझदारी पर निर्भर है। सरकार ने ये दिशानिर्देश भी जारी किए हैं कि अब ये संस्थान अच्छी एवं बेहतर रैंकिंग एवं अच्छे बेहतर नंबर की गारंटी भी नहीं दे सकेंगे। अक्सर कोचिंग संस्थान गुमराह करने वाले बड़े-बड़े विज्ञापनों में ऐसे ही दावे करते हैं। कई कोचिंग संस्थानों में बच्चों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वे इन बच्चों को भर्ती तो कर लेते हैं पर पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं रहता है। कई बार कोचिंग सेंटर अच्छे ना होने से भी उनमें दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। आग लगने की कुछ दुघर्टनाएं भी कोचिंग सेंटरों में हुई हैं।

मनमोहन राजावतराज, शाजापुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति और अन्य क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर हिंद महासागर पर केंद्रित दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हैं।

कल्पमेधा

कोई भी सुधार तभी हुआ है, जब साहसी व्यक्तियों ने समाज में प्रचलित अमानवीय प्रथाएं और रीति-रिवाज स्वयं तोड़ डाले हों।

- गांधी

अतिक्रमण की जमीन

उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने की कोशिश में जिस तरह हिंसा भड़क उठी और बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के घायल होने तथा हिंसा पर उतारू भीड़ पर गोली चलाने से चार लोगों के मारे जाने की खबर आई, उससे अतिक्रमण रोकने के सरकारी प्रयासों पर एक बार फिर गहरा सवालिया निशान लगा है। गौरतलब है कि हल्द्वानी के एक इलाके में सरकारी भूखंड पर कथित रूप से कब्जा कर मजार और मदरसा बना लिया गया था। उसे हटाने के लिए पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी वहां पहुंचे तो स्थानीय लोग उग्र हो उठे और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। अब स्थिति यह है कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि भीड़ के उग्र और हिंसक होने के पीछे क्या कोई साजिश है! इसी तरह पिछले वर्ष जनवरी में भी हल्द्वानी के ही एक इलाके में रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बसी एक बस्ती को हटाने का अभियान चलाया गया था। तब भी खासा हंगामा हुआ। अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उस मामले को मानवीय करार देते हुए अदालत ने बेदखली पर रोक लगा दी थी। हल्द्वानी में और भी ऐसी जगहें हैं, जहां लोगों ने अतिक्रमण कर बस्तियां या मकान-दुकान बना ली है।

पिछले वर्ष भी वन विभाग, रेलवे और राजस्व विभाग के भूखंडों पर से अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया गया था। पता चला कि कई जगहों पर भूमाफिया ने सौ और पांच सौ रुपए के स्टांप पर लोगों को सरकारी जमीन बेच दी थी। उन पर लोग घर बना कर रह रहे हैं। उनमें से ज्यादातर स्थानीय निवासी नहीं हैं। वे वहां मजदूरी वगैरह करने के लिए गए थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारी भूखंड पर किसी को अवैध रूप से कब्जा कर रिहाइश या कोई कारोबारी भवन बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मगर यह सवाल अपनी जगह है कि प्रशासन और सरकार को तभी ऐसी जगहों को खाली कराने की सुध क्यों आती है, जब लोग वहां बस्तियां बसा चुके होते हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा शहर हो, जहां अवैध रूप से कायम की गई बस्तियां आबाद न हों। ये बस्तियां कोई एक दिन में या रोतोंरात तो बस नहीं जातीं। कहीं-कहीं तो लोग दावे करते हैं कि वे पचास-पचास वर्ष से रह रहे हैं।

सरकारी भूखंडों पर कब्जे की प्रवृत्ति पुरानी और उजागर है। इसके पीछे सक्रिय लोग भी करीब-करीब पहचाने हुए होते हैं। सरकारी अमले और भूमाफिया के बीच गठजोड़ के जरिए अतिक्रमण कराया जाता है। फरीदाबाद के वनक्षेत्र में वर्षों से आबाद हजारों लोगों की बस्ती को भी इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हटाना पड़ा था। ऐसे मामलों में ठगे और मारे जाते हैं, वे गरीब लोग, जिन्हें धोखे में रख कर भूमाफिया कम कीमत पर जमीन बेच देते हैं। यही नहीं, कई जगह तो बस्तियां बसने के बाद उनमें बिजली-पानी की सुविधाएं भी सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध करा दी जाती हैं। लोग राशन कार्ड, आधार पहचान-पत्र जैसे दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं। तब प्रशासन को यह जरूरी क्यों नहीं लगता कि वह वहां बस रहे लोगों को रोके। किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को हटाया ही जाना चाहिए, मगर उसका तरीका कानूनी होना चाहिए, ताकि हिंसा की नौबत न आने पाए।

अपराध और दुस्साहस

मुंबई में फेसबुक पर सीधे प्रसारण के दौरान शिवसेना (यूबीटी) के एक पूर्व विधायक के बेटे की जिस तरह गोली मार कर हत्या कर दी गई, वह अपने आप में एक दहला देने वाली घटना है। इसमें हत्या करने वाले व्यवसायी ने खुद को भी गोली मार कर खुदकुशी कर ली। इसलिए यह मामला बेहद उलझ गया लगता है। हालांकि शुरुआती जांच के मुताबिक दोनों में लंबे समय से निजी दुश्मनी थी और इसी प्रतिद्वंद्विता में उनके बीच पहले भी टकराव हो चुके थे, मगर वह एक-दूसरे के लिए परेशानी पैदा करने तक सीमित था। कुछ समय पहले दोनों के बीच सुलह हो गई थी और उन्होंने अपने इलाके के हित के लिए मिल कर काम करने की घोषणा की थी। मगर ताजा घटना से यह साफ है कि पहले की दुश्मनी इस हद तक थी और उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि फेसबुक पर बातचीत के सीधे प्रसारण के दौरान हत्या की यह त्रासद घटना हुई। संभव है कि इस वाकये की जांच में कुछ प्रत्यक्ष कारणों से इतर कुछ और वजहें भी सामने आएं, मगर इतना साफ है कि मरने वाले दोनों लोगों के बीच संबंधों में जैसी तल्खी थी, उसका अंजाम कुछ भी हो सकता था।

हालांकि राजनीति की दुनिया में कब आपसी टकराव दुश्मनी की शक्ल ले ले या फिर आम लोगों को चौंकाते हुए सुलह सामने आ जाए, कहा नहीं जा सकता। हाल ही में महाराष्ट्र के ही उल्हासनगर में एक भाजपा विधायक और उसके एक साथी ने जमीन विवाद की वजह से एकनाथ शिंदे के गुट वाले शिवसेना के एक नेता पर पुलिस थाने के भीतर गोलीबारी कर दी थी। इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अब जिस तरह बिना किसी हिचक के सार्वजनिक रूप से अंजाम दिया जा रहा है, उससे लगता है कि कानून-व्यवस्था का खौफ खत्म हो गया है। सोशल मीडिया पर बातचीत के सीधे प्रसारण के दौरान हत्या की घटना यह बताती है कि जब दुश्मनी का रूप बेहद जटिल हो जाता है, तब शायद बहुत सोच-समझ कर ऐसा तरीका आजमाया जाता है, जो व्यापक पैमाने पर लोगों पर असर डाले। अपराध की यह बदलती प्रकृति सरकार और पुलिस-प्रशासन के लिए एक चुनौती है कि इनसे कैसे निपटा जाए। मगर कानून का खौफ कायम कर अपराध की रोकथाम भी संभव है।

तनाव के विरुद्ध लड़ने की शिक्षा

शिक्षा के बाजारीकरण ने शिक्षा को लाभ केंद्रित व्यवसाय बना दिया है। जहां लाभ कमाना प्रमुख लक्ष्य होता है, वहां सार्वजनिक हित या कल्याण की बात सोचना उचित प्रतीत नहीं होता।

ज्योति सिडाना

शिक्षा का उद्देश्य तनाव देना नहीं, बल्कि तनाव को दूर भगाना होता है। जब शिक्षा तनाव देने का माध्यम बन जाए, तो वह उद्देश्यहीन हो जाती है। पिछले कुछ सालों से ऐसा लगने लगा है कि शिक्षा विद्यार्थियों में दबाव, कुंठा और पलायन की प्रवृत्ति विकसित कर रही है। शायद यही कारण है कि किशोरों और युवाओं में आत्महत्या की दर बढ़ रही है। पिछले वर्ष केवल कोटा में उनतीस विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली और इस साल के पहले महीने में ही वहां दो विद्यार्थियों ने खुद को फंदे पर लटका दिया, जोकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि शिक्षा विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करना, जीवन में संघर्ष करना सिखाती है, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना और संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात कर समाज का एक सभ्य नागरिक बनना सिखाती है। पर आत्महत्याओं की संख्या में होती वृद्धि तो कुछ और ही कहानी कहती है।

दरअसल, शिक्षा के बाजारीकरण ने शिक्षा को लाभ केंद्रित व्यवसाय बना दिया है। जहां लाभ कमाना प्रमुख लक्ष्य होता है, वहां सार्वजनिक हित या कल्याण की बात सोचना उचित प्रतीत नहीं होता। एक रपट के अनुसार देश में इस वक्त कोचिंग उद्योग करीब 58,088 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2028 तक इसके 1,33,995 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाने का अनुमान है। विचार का विषय यह है कि आखिर क्यों इन कोचिंग संस्थानों का बाजार इतना फल-फूल रहा है। क्या विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा देने में असमर्थ हो गए हैं या वे बाजार की मांग के अनुरूप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और बच्चों को बाध्य होकर कोचिंग में जाना पड़ता है।

इसमें संदेह नहीं कि जबसे शिक्षण संस्थान उद्योग के रूप में उभर कर आए हैं और उद्योगपतियों ने शिक्षा को एक उत्पाद के रूप में क्रय-विक्रय की वस्तु बना दिया, तब से शिक्षा बाजार की जरूरतों के हिसाब से दी जाने लगी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार के अनुरूप शिक्षा समाज के विरुद्ध शिक्षा बनती जा रही है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा बच्चों में पलायनवाद की प्रवृत्ति को विकसित कर रही है। वे अपने पहले प्रयास में ही सफलता के उच्चतम शिखर को छूने की आकांक्षा रखते हैं और ऐसा न होने पर स्वयं को समाप्त करने से भी नहीं चूकते। इस बाजारवाद के दौर में शिक्षा महंगी और जान सस्ती हो गई है। पहले के समाजों में जब परिवारों का आकार बड़ा होता था और व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अनेक संघर्ष करने पड़ते थे, तब भी वे आत्महत्या के बारे में नहीं सोचते थे। हर समस्या का सामना सूझ-बूझ और सामूहिक प्रयास से करने की कोशिश करते थे। मगर आज की किशोर और युवा पीढ़ी मानो जीवन जीना ही नहीं जानती।

इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण हमारी शिक्षण प्रणाली भी है। स्कूल में बच्चे केवल प्रतिस्पर्धा करना नहीं सीखते, बल्कि समूह में कार्य करना, अपनी टीम का नेतृत्व करना, निर्णय लेना, मस्ती करना, लीक से हट कर सोचना, खेलना-कूदना, मित्रों के साथ त्योहार और उत्सव मनाना, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में सहभागिता करना और समाज में व्याप्त विविधता को भी सीखते हैं। मगर अब छोटी-छोटी उम्र में कोचिंग का हिस्सा बनना और गलाकाट प्रतिस्पर्धा में शामिल होने से बच्चे इन सब गतिविधियों से वंचित होते जा रहे हैं। उन्हें अपने सहपाठियों में मित्र नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी नजर आते हैं।

स्कूल में बच्चे केवल प्रतिस्पर्धा करना नहीं सीखते, बल्कि समूह में कार्य करना, अपनी टीम का नेतृत्व करना, निर्णय लेना, मस्ती करना, लीक से हट कर सोचना, खेलना-कूदना, मित्रों के साथ त्योहार और उत्सव मनाना, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में सहभागिता करना और समाज में व्याप्त विविधता को भी सीखते हैं। मगर अब छोटी-छोटी उम्र में कोचिंग का हिस्सा बनने और गलाकाट प्रतिस्पर्धा में शामिल होने से बच्चे इन सब गतिविधियों से वंचित होते जा रहे हैं। उन्हें अपने सहपाठियों में मित्र नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी नजर आते हैं।

नतीजतन, वे अपने मन की बातों को भी आपस में साझा नहीं कर पाते और तनाव में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिनके परिणाम से संभवतः वे अवगत भी नहीं होते।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे शिक्षा और ज्ञान व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी होते हैं, वैसे ही सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेलकूद संबंधी गतिविधियां भी व्यक्तित्व विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्कूल में बच्चों को इन सब गतिविधियों का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, लेकिन कोचिंग में नहीं। यही कारण है कि कोचिंग में पढ़ रहे बच्चे स्कूल से कहीं ज्यादा तनाव में होते हैं। स्कूल में बच्चों के दोस्त होते हैं, जिनके साथ वे अपनी समस्याओं को साझा करके पढ़ाई का तनाव कम कर लेते हैं, लेकिन कोचिंग में बच्चे दोस्त नहीं बना पाते, क्योंकि उन्हें हर किसी में प्रतिस्पर्धी नजर आता है। उन्हें केवल पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए निर्देशित किया जाता है, बाकी सभी गतिविधियों को उपेक्षित करने की सलाह दी जाती है।

शायद पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षा में सफलता को ही वे जीवन और विफलता को मृत्यु समझने लगते हैं। ऐसी शिक्षा किस काम की, जो बच्चों पर इतना दबाव डाले कि वे दबाव को न झेल पाने के कारण आत्महत्या तक कर लें। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार अब कोई कोचिंग संस्थान सोलह साल से कम उम्र के छात्र का नामांकन नहीं कर सकता। सिर्फ माध्यमिक की परीक्षा के बाद ही नामांकन करना होगा। साथ ही अब कोचिंग संस्थान अच्छी रैंक और गुमराह करने वाले वादे भी नहीं कर सकते। अगर कोई संस्थान ऐसा करता है तो पहली बार पच्चीस हजार रुपए, फिर एक लाख रुपए के दंड का भागी होगा और जरूरत पड़ने पर उस संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। इसे एक सकारात्मक और महत्त्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। हालांकि ऐसे दिशा-निर्देश पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनकी पालना आज तक नहीं हो पाई। इसलिए कि दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य नहीं मानी जाती। अगर निर्देशों को कठोरता से लिया जाता, तो अब तक इस दिशा में कुछ तो सुधार हो गया होता। इसलिए कठोर नियम बनाने की जरूरत है, ताकि शिक्षा को बाजार में लाभ की वस्तु बनने से रोका जा सके।

नेल्सन मंडेला का मानना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मिशेल फूको मानते हैं कि ज्ञान शक्ति है। अगर ऐसा है तो फिर अधिकतर शिक्षित व्यक्ति ही आत्महत्या जैसे कदम क्यों उठाते हैं। आज के समय में ज्ञान और शिक्षा का जितना अधिक विस्तार हुआ है, ऐसा लगता है कि युवाओं में चुनौतियों का सामना करने या संघर्ष करने की क्षमता भी कम हुई है। वे बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, इसलिए जरूरत है कि सरकार, प्रशासन, शिक्षक, बुद्धिजीवी सभी पाठ्यक्रमों और शिक्षा नीति का निर्माण करते समय इन सभी पक्षों पर गंभीर चिंतन करें और बाजार की मांग या जरूरत के अनुरूप नहीं, बल्कि विद्यार्थी और समाज की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करें। बच्चों को रोजगार केंद्रित या केवल तथ्यों/ सूचनाओं को एकत्र करने वाली शिक्षा के लिए प्रेरित न करें, बल्कि मानवता और सामाजिकता सीखने और जीवन में संघर्ष करने का जज्बा विकसित करने का पाठ सीखने के लिए प्रेरित करें।

सुबह का संगीत

राकेश सोहम्

सुबह में कहां कोई संगीत होता है? वह तो अलसाए अंधेरे में लिपटी, चुपचाप होती है। सुबह देर तक सोने वाली अधुनातन पीढ़ी यही मानती है। बिस्तर पर पड़े रहने के आदी बहुत सारे लोगों का मानना है कि सुबह भ्रमण के लिए वही लोग निकलते हैं जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। अनिद्रा के शिकार लोग भी सुबह का संकेत मिलते ही बिस्तर छोड़कर भाग निकलते हैं। पालतू कुत्ते को सुबह घुमाने की मजबूरी लोगों को देर तक सोने नहीं देती। सेवानिवृत्त फुरसतिया लोग सुबह की खाली सड़कों पर और पार्क में वक्त काटने निकलते हैं। दरअसल, ऐसी सोच सुबह देर तक सोने वालों को आत्म तुष्टि देती है। आधुनिक पीढ़ी प्रतिस्पर्धात्मक जीवन जी रही है। ऐसे लोग पिछले दिन की असफलता के साथ सुबह देर तक अवसाद में पड़े रहते हैं। उन्हें सुबह मनहूस दिखाई देती है। मजबूरी में सुबह जल्दी उठ जाएं तो दिन इतना लंबा लगने लगता है कि काटना मुश्किल हो जाता है। वे जम्हाई लेते बुझे-बुझे से कहते फिरते हैं कि आज का दिन ही बर्बाद हो गया। अक्सर देर रात सोने के मानवीय स्वभाव, अनैतिक चिंतन और बेमतलबी उलझन का इल्जाम बेचारी सुबह झेलती है। लोगों का वश चले तो सुबह को होने ही न दें। दिन की शुरुआत दोपहर से होने लगे। कुछ आलसी लोग 'जब जागे तभी सवेरा' का मतलब इन्हीं अर्थों में लेते हैं।

ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो सुबह उठते हैं और बीते दिवस की सारी चिंताओं का बोझ लेकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ये लोग प्रकृति के संगीत को नहीं सुन पाते! अनेक ऐसे शहर में हैं, जहां रिहाइशी क्षेत्रों के आसपास हरियाली का अभाव है। खुले मैदानों की कमी है। विकसित उद्यान या पार्क नहीं हैं। सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में लोग प्रातः भ्रमण के लिए कहां जाएं? एक सतासी वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर ऐसी ही एक बस्ती में पत्नी के साथ अकेले रहते हैं। इस उम्र में भी वे पूरी तरह स्वास्थ्य, चैतन्य और स्फूर्ति से भरे हुए हैं। आज भी दोपहिया वाहन और कार पूरी मुस्तैदी से चलाते हैं। उन्हें याद नहीं पड़ता कि कब वे सुबह भ्रमण के लिए नहीं गए। शहर में अपने घर पर हैं तो प्रातः भ्रमण की चूक नहीं होती। ठंड, गर्मी, बरसात- कोई भी मौसम उनके घूमने में आड़े नहीं आता। ठंड में आवश्यक गर्म कपड़े पहनकर और बरसात में छाता लेकर निकलते हैं।

इस तरह के लोग किसी को अपने आसपास भी मिल सकते हैं, जो नित्य सुबह चार बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। पड़ोस के वे बुजुर्ग सुबह एक गिलास गुनगुना पानी पीते हैं। ताजा होने के बाद एक प्याला नींबू चाय पीते हैं और प्रातः भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। उनके घर के आसपास न पार्क है, न हरियाली और न कोई मैदान। शहर के खाली रास्ते के किनारे-किनारे दूर तक पैदल निकल जाते हैं। वे इस दौरान मोबाइल के उपयोग से बचते हैं। न कोई संगीत, प्रवचन या भजन सुनते हैं और न ही किसी से बातचीत करते हैं। एक साक्षी भाव मन में रखते हैं।

आसपास जो है, उसे ऊपर बैठी परम सत्ता की अनुपम कृति मानने का अपना सुख है और आत्मसात कर लेना शांति की राह। जो है, जैसा है, अपना है। इस जीवन का हिस्सा है। चीजें, वस्तुएं, प्राकृतिक हों या फिर भौतिक, उसमें तिरोहित हो जाना जीवन को संपूर्णता में जीने का जरिया है। गौर से सुना जाए तो सुबह की नीरवता में भोर का संगीत सुनाई देने लगता है। शुद्ध हवा के झोंके महसूस हो सकते हैं। पंछियों की आवाज अंदर उतरने लगती है। अपनी ही पदचाप हमें चेतावनी देती है। सूर्य की नरम किरणें रात के खुमार को धकेल देती हैं। ऐसे में जब लौटा जाए, तो मन आनंद की ऊर्जा से भरपूर रहता है। एक चाय का प्याला हाथ में लेकर अखबार या कोई पसंदीदा किताब पढ़ने का अपना सुख है। मोबाइल पर संदेशों का आदान-प्रदान सरोकारी होने का सूचक है। मन आया तो लिखने बैठ गए।

किसी भी व्यक्ति की ऐसी दिनचर्या प्रेरणादायक होती है। लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की मिसाल है। हिंदी फिल्म 'बूंद जो बन गई मोती' में एक खूबसूरत गीत है, जो सुबह की खामोशी में प्रकृति के संगीत को महसूस कराता है- 'हरी भरी वसुंधरा पर नीला नीला ये गगन, कि जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी चमक रहीं उमंग भरी। ये किसने फूल फूल से किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है...।' यह उस दौर का गीत है, जब भरपूर प्राकृतिक नजारे हमारे आसपास थे।

आज शहरी इलाकों से प्रकृति लगभग पलायन कर चुकी है। आसपास बनावटी प्रकृति ने डेरा जमा लिया है। आधुनिकता, विज्ञान और विकास के भय से वह शहरों से दूर चली गई है। ऐसे में इस तरह के विचारों से संतोष मिलता है कि हमारे चारों ओर जो कुछ है, वह प्रकृति है। आसपास ही क्यों, हम स्वयं प्रकृति हैं। अगर हम अपने अंदर झांक सकें तो प्रकृति को ही पाएंगे। मानव इस विराट प्रकृति का हिस्सा है। बस सुबह के संगीत को महसूस करें। इसका आनंद अप्रतिम है।

दुनिया मेरे आगे

आज शहरी इलाकों से प्रकृति लगभग पलायन कर चुकी है। आसपास बनावटी प्रकृति ने डेरा जमा लिया है। आधुनिकता, विज्ञान और विकास के भय से वह शहरों से दूर जा चुकी है। ऐसे में इस तरह के विचारों से संतोष मिलता है कि हमारे चारों ओर जो कुछ है, वह प्रकृति है।

मैदान में दमखम

दूसरे क्रिकेट टैस्ट मैच के चौथे दिन विशाखापट्टनम में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड टीम को शानदार गेंदबाजी की बदौलत 102 रनों से हरा दिया। क्रिकेट अनिश्चितता भरा खेल है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है। टीम का हर खिलाड़ी मैच का पांसा पलटने में सक्षम है। पर यह टीम विश्वकप जैसे अहम मुकाबले में अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल प्रदर्शन नहीं कर पाती। प्रबंधन को खिलाड़ियों में आत्मविश्वास जगाना चाहिए और उन्हें अच्छे खेल के लिए उत्साहित करना चाहिए। सबसे बड़ी कमी चयनकर्ताओं और प्रबंधन दल की है, जो अच्छे खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं देते। क्रिकेट के हर प्रारूप में विश्व विजेता बनना है तो गेंदबाजों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बल्लेबाजों की कमियों को दूर करने की ओर ध्यान देना चाहिए। खड़े-खड़े गेंदों पर बल्ला अड़ाने, खराब गेंदों का इंतजार, जोरदार बल्लेबाजी करने वाले का रक्षात्मक होना- इन कमियों को सुधार कर चपल 'फुटवर्क' की ओर ध्यान दिलाना चाहिए, ताकि भारत टैस्ट मैच ही नहीं, आने वाली सभी प्रतियोगिताओं में जीत का परचम लहराए।

- कुलदीप मोहन त्रिवेदी, उन्नाव, उप्र

जोखिम की आतिशबाजी

हाल ही में मध्यप्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से ग्यारह लोगों की मौत और करीब पौने दो सौ लोगों के घायल होने की खबर आई। विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर तक गई। एक खबर के मुताबिक, कारखाने में पांच सौ से ज्यादा लोग काम करते थे। यानी यह कारखाना काफी बड़ा था। हमारे देश में पटाखा व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है। पहले पटाखों का संबंध दिवाली के साथ ही ज्यादा होता था। अब तो शादी, जन्मदिन, नए साल का जश्न, चुनावी परिणाम और क्रिकेट मैच आदि के परिणामों पर भी लोग बहुतायत से पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसे घटनाएं होती हैं कि छोटे बच्चों या कभी-कभी बड़े भी पटाखे चलाते समय दुघर्टना का शिकार हो जाते हैं।

ऐसी स्थिति में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि हम पटाखों के इस्तेमाल पर खुद ही रोक लगाएं। आमतौर पर हम देखते हैं कि दिवाली के तुरंत बाद ही पटाखों के कारण प्रदूषण बढ़ जाता है। अब भी समय है कि सरकार और समाज, दोनों ही पटाखों के जोखिम और पर्यावरणीय नुकसान पर नियंत्रण करने के लिए संज्ञान लें।

- शिवनारायण गौर, भोपाल

प्रकृति के साथ

प्रगति के साथ-साथ अधिक फसल लेने के लिए सभी किसान जमकर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। गत दो दशक से इनका का भरपूर प्रयोग हो रहा है, जिसके चलते धरती अपनी उर्वरता खो रही है। विषैले रसायनों के धरती के भीतर निरंतर जाते रहने से पानी दूषित हो रहा है। फसलें अधिक मात्रा में उगती हैं, पर उनमें वह स्वाद और ताकत नहीं रही। अब फिर से लोग प्राकृतिक तरीके से या जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इससे करोड़ों रुपए का कीटनाशक और खाद की बचत होगी। जैविक फसल अधिक दाम में बिकने के कारण किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा और धरती स्वच्छ रहेगी, वातावरण स्वच्छ रहेगा। धरती के भीतर का जल शुद्ध होगा और लोग बीमारियों से बचेंगे!

- विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

बर्बादी का भोजन

खाने की कीमत उससे पूछना चाहिए, जिसे पेट भरने के लिए दो वक्त की रोटी या तो नसीब नहीं होती है या बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक यह सुझाव दिया है कि विद्यार्थियों को खाने की बर्बादी से होने वाले नुकसानों को समझाने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम में एक अध्याय इससे संबंधित जरूर शामिल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र की एक रपट अनुसार सारी दुनिया में 2019 में लगभग 93 करोड़ 10 लाख टन खाना बर्बाद हो गया। हमारे देश में भी खाने की बहुत बर्बादी होती है। दूसरी तरफ देश में भी भूखे पेट सोने वाले गरीब लोगों का आंकड़ा कोई कम नहीं है। हमारे यहां बच्चों में कुपोषण की समस्या गहरी है। जिनके दिल-दिमाग पर धन ने पट्टी बांधी हो, वे भोजन की क्या कद्र करेंगे!

- राजेश कुमार चौहान, जलंधर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जैसा तीखा राजनीतिक विभाजन दिखाया जाता रहा है, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक रूप से देखें तो धर्म और संस्कृति की एक समान धारा बहती है। विश्वनाथ मंदिर के गलियारे में इडली-सांबर की दुकानों के बीच 'प्राचीन काल' से वहां बसे अन्ना बताएंगे कि उत्तर भारत स्थित शिव की इस नगरी की दक्षिण भारत में कितनी आस्था है। आज उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीतिक फसल काट ही नहीं पाती अगर दक्षिण से शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को सांस्थानिक रूप नहीं दिया होता। भारत के भूगोल की चारों दिशाओं पर पीठ स्थापित कर उन्होंने हिंदू धर्म को मानक संस्थान दिया। शंकराचार्य ने कम उम्र में जिस दैवीय गति से देश की चारों दिशाओं का भ्रमण कर एकात्म हिंदू धर्म की ध्वजा फहराई उसी की देन है कि भाजपा के आदि पुरुष आडवाणी रथयात्रा शुरू कर सके। चुनावी मौसम में देश की दो दिशाओं की राजनीतिक बहस के मद्देनजर उत्तर व दक्षिण भारत को धार्मिक व सांस्कृतिक पुल से जोड़ने वाले शंकराचार्य की विरासत पर बेबाक बोल।

बेबाक बोल

शंकर सेतु

मुकेश भारद्वाज

हिंदी हृदय प्रदेश में भाजपा की बंपर जीत के बाद विपक्ष ने दक्षिण को लेकर उम्मीद जताई। वहीं संसद के बजट सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को उत्तर-दक्षिण में बांटने की बातें बंद हों। लोकसभा चुनाव के पहले 2024-25 के अंतरिम बजट पर हैरानी जताई गई। 2019 में जब राजग सरकार ने वोटरों को आकर्षित करने के लिए अंतरिम बजट का भरपूर इस्तेमाल किया था तो 2024 का अंतरिम बजट शब्दशः अंतरिम क्यों है? क्या इसका एक कारण राम मंदिर से मिला आत्मविश्वास है? अब सवाल है कि दक्षिण में बंद कपाट की कुंजी भाजपा कहां से लाएगी?

इस सवाल के जवाब के लिए चलते हैं केदारनाथ और ओंकारेश्वर। केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री संदेश दे ही चुके थे। वहीं ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का आधिकारिक नाम 'स्टैच्यू आफ वननेस' है। जो उत्तर में राम को लाने का दावा कर रहे हैं उनके लिए दक्षिण में जाने के लिए धर्म सेतु तो हिंदू धर्म के आदि-पुरुष शंकराचार्य बना चुके थे।

आज हम जिस 'हिंदू धर्म' की बात करते हैं वह एक धार्मिक संस्थागत रूप में है तो इसकी आधारशिला शंकराचार्य ने रखी थी। 1984 में दो संसदीय सीटों पर सिमटी भाजपा के आदि-पुरुष ने इसी 'एकात्मता' को साधने का प्रयोग किया जो राजनीति की परखनली में 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत का उत्पाद लाया। भाजपा के संस्थापक सदस्य रथयात्रा निकाल ही नहीं पाते अगर शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को सांस्थानिक रूप नहीं दिया होता। आज अगर उत्तर भारत के मंदिर में श्रीराम की श्यामवर्ण प्रतिमा उत्तर से दक्षिण की संस्कृति का गठबंधन है तो इसकी गांठ बांधने वाले शंकराचार्य थे।

भाजपा के आदि-पुरुष लालकृष्ण आडवाणी आज 'भारत-रत्न' हैं तो इसलिए कि उन्होंने समझ लिया था कि भारत जैसे आस्थावान देश में धर्म हिंदुओं का निजी विषय नहीं हो सकता है। धर्म का उदय ही परिवार और समाज को सांस्थानिक रूप देने के लिए हुआ। मूल रूप से धर्म और आस्था निजता की सीमा के परे सामाजिकता के समीकरण से आए थे।

भारतीय संदर्भ में देखें तो यहां धार्मिक एकता परिभाषित नहीं थी। इसकी परिभाषा की पाठशाला के आदि अध्यापक शंकराचार्य हैं। उत्तर भारत में भले ही शंकराचार्य के उत्तराधिकारियों पर तात्कालिक विवाद खड़ा कर दिया गया, लेकिन ओंकारेश्वर में खड़ी की गई आदि पुरुष की 108 फुट की मूर्ति कह रही है कि उसे भाजपा के विमर्श गढ़ने पर पूरा भरोसा है। वह दक्षिण भारत में उसी समझदारी के साथ जाएगी जिस तरह से अस्सी के दशक में उत्तर भारत में आई थी। काशी तमिल संगमम से लेकर रामेश्वरम तक में स्नान बता रहा है कि आदि शंकराचार्य की खड़ी की गई हिंदू धर्म की संस्था एकात्मक रूप में ही आगे बढ़ाई जा सकती है।

भारत और उससे जुड़े सनातन धर्म के लिए सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है-विविधता में एकता। हिंदू धर्म में इतनी सारी विविधता के साथ एकात्मता की खूबसूरती लाने वाले थे शंकराचार्य। वैदिक धर्म की वर्णव्यवस्था, ब्राह्मण धर्म का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण में एक जैसा नहीं था। आज उत्तर और दक्षिण भारत के हिंदू धर्म की एकता के बीच में शंकराचार्य हैं जो पहली बार धर्म को संगठित कर रहे थे। वैदिक धर्म के ज्ञान को संग्रहित कर शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की धार्मिक व सांस्कृतिक पूंजी को सुरक्षित किया।

शंकराचार्य ने शिव के जरिए भारत के भौगोलिक नक्शे पर चार धाम स्थापित किए। इन चार धामों को भारत की धार्मिक अस्मिता की चौहद्दी बना कर उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार-प्रसार किया। धर्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने भ्रमण और अध्ययन का सहारा लिया। शंकराचार्य वाद-विवाद और तर्क के लिए जाने जाते हैं। तर्क और शास्त्रार्थ की शुरुआत ही इसलिए हुई ताकि धर्म पर बहस कर उसे लेकर जनमत का निर्माण हो। शास्त्रार्थ में जीत-हार व्यक्तिगत स्तर पर तय करना मुश्किल होता था, लेकिन धर्म और उसकी मान्यताओं का जीतना और आगे बढ़ना तय होता था। उन्होंने विरोधी पंथ की बातों को संयम से सुना और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का खाका खींचा।

शंकराचार्य और शास्त्रार्थ की दंतकथाओं पर ही नजर डालेंगे तो किस तरह गृहणियों तक ने शास्त्रार्थ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और आदि पुरुष के धार्मिक ज्ञान को चुनौती दी। धर्म और उसके शास्त्र को लोककथाओं तक पहुंचा कर शंकराचार्य ने उसे इतिहास की स्मृति का हिस्सा बना दिया। वे अपने भ्रमण मार्ग पर हिंदू धर्म को मील का पत्थर की तरह स्थापित करते चले गए।

हम उस समाज की कल्पना करें, जहां ज्ञान-विज्ञान घर-घर में बिखरा हुआ हो लेकिन वहां विद्यालय जैसा कोई सामूहिक संस्थान नहीं हो। फिर उस समाज के लोग किस तरह से समान इतिहास, विज्ञान और साहित्य पढ़ पाएंगे। इसके पहले हिंदू धर्म की यही स्थिति थी। अन्य धर्मों का प्रभाव तात्कालिक समय पर पड़ चुका था और ऐसी कोई पाठशाला नहीं थी जहां से हिंदू धर्म के लोग धर्म के मानकीकृत रूप का प्रमाणपत्र लेकर आएं। वेदों के प्रति अनास्था का दौर आ गया था।

जिन वेदों की उत्पत्ति करोड़ों साल पहले की बताई गई उसकी ऋचाएं विस्मृत हो रही थी। षट दर्शन, जैन, बौद्ध, चार्वाक के दर्शनों की गूंज चहुंदिशा में थी। बौद्ध धर्म हिंदू शासकों के आकर्षण का नया केंद्र बन चुका था। इसलिए आम जनता भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। जब शासक ही आदि धर्म से विमुख हो जाए तो फिर उसे कौन बचाता? केंद्रीय धर्म के अभाव में भारत के भूगोल की परिधि में एक अराजकता की स्थिति सी आ चुकी थी।

शंकराचार्य के चार मठ न होते तो शायद सब कुछ आज इतने समृद्ध और सतत रूप में नहीं बचता। शंकराचार्य ने भारत के भूगोल की चारों दिशाओं पर मठ स्थापित कर हिंदू धर्म को मानकीकृत करने का स्कूल खोल दिया था। अब चारों दिशाओं के लोग हिंदू धर्म का एकरूप पाठ पढ़ सकते थे।

सत्ताधारी राजनीति धर्म, संस्कृति की लंबी परंपरा का हवाला देकर धार्मिक आस्था को मूल विषय बना चुकी है। श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अबकी बार चार सौ पार का दावा कर रही है। इसके लिए धर्म की फसल काटना इतना आसान नहीं होता अगर देश के चारों कोनों पर शंकर आराध्य नहीं बन चुके होते। आज जिसे हम राम-पथ कह रहे रहे हैं उसकी बुनियाद में शिव के अलग-अलग रूप हैं। शिव और शक्ति इन दोनों के आधार पर अलग-अलग देवी-देवता हुए, धार्मिक परंपराएं हुईं। शिव को आधार बना कर शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को संगठित शक्ति बनाया।

हिंदुओं के ज्यादातर प्राचीन देवालय शिव और शक्ति (दुर्गा, काली के रूप) के हैं। श्रीराम के प्राचीन देवालय इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि वो अवतार हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक साहित्य के सगुण से लेकर निर्गुण रूप तक श्रीराम की अखिल भारतीय व्याप्ति रही है।

हिंदू धर्म वह विचार है जिसे शंकराचार्य ने सैकड़ों साल पहले संगठित कर लिया था। हिंदू धर्म का उदय अचानक से 1980 के बाद नहीं हुआ था। हां, 1980 के बाद राजनीति का वह स्कूल स्थापित हुआ जिसने शंकराचार्य के स्थापित स्कूल की अहमियत समझी थी। पिछले दिनों हिंदू धर्म की वैचारिक विरासत को जिस तरह आदि पुरुष के उत्तराधिकारियों से काटने की कोशिश की गई वह राजनीतिक टकराहट में अपनी टक्कर को जोरदार करने का क्षणिक प्रपंच भर था। उत्तर भारत के हृदय प्रदेशों के विजेता जब दक्षिण के दुर्ग में प्रवेश करेंगे तो वहां के कपाट की कुंजी भारत के उत्तर और दक्षिण को एकात्म धार्मिक हृदय देने वाले शंकराचार्य ही होंगे।

अब नैतिकता?

बिहार में भाजपा और जद (एकी) गठबंधन की सरकार को सदन में बहुमत साबित करना अभी बाकी है। नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में 12 फरवरी को मतदान होगा। राजग सरकार विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आशंकित है। अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ठहरे राजद के नेता। जद (एकी) और भाजपा के विधायकों ने उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की थी। पर चौधरी ने साफ इनकार कर दिया। फरमाया कि वे नीतीश सरकार के सदन में बहुमत साबित कर देने के बाद ही पद छोड़ने के बारे में फैसला करेंगे। हालांकि जद (एकी) विधायकों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है। नियमानुसार अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर अध्यक्ष को फैसला करना जरूरी है। चौधरी ने कहा कि उन्हें तो इस अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी आठ फरवरी को ही मिली है। लिहाजा 12 फरवरी को सदन की कार्यवाही का संचालन वे ही करेंगे। राजद का दावा है कि जद (एकी) और जीतनराम मांझी की पार्टी के कई विधायक उसके संपर्क में हैं। भाजपा को अपने गिरेबां में भी झांकना चाहिए। उसे छोड़कर 2022 में नीतीश ने जब राजद के साथ साझा सरकार बनाई थी तब विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भाजपा के थे। राजद की इस्तीफे की मांग उन्होंने ठुकरा दी थी। अब राजग के लोग अवध बिहारी चौधरी को नैतिकता का पाठ किस मुंह से पढ़ा सकते हैं।

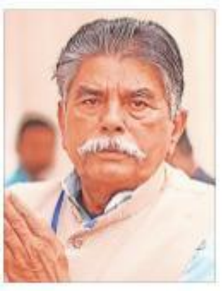

ममता के बहाने

भाजपा कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। अब उसे ममता बनर्जी ने और मुद्दा थमा दिया। फरमाया कि कांग्रेस वाराणसी में नरेंद्र मोदी को हराकर दिखाए। और आगे जाकर यहां तक बोल दिया कि 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। ममता भूल गईं कि वे खुद को चाहे जितना बड़ा नेता समझती हों पर विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में उन्हीं के पुराने चेले सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा उम्मीदवार की हैसियत से 2021 में उन्हें धूल चटाई थी। बहरहाल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे थे तो उल्लेख ममता बनर्जी के बयान का ही कर रहे थे कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलने वाली। इतने विरोधाभासों वाले गठबंधन की विश्वसनीयता पर किसे संदेह नहीं होगा? देखना है अब यह गठबंधन और क्या बुरा देखता है।

राजपाट

उपराष्ट्रपति को बधाई

राज्यसभा में राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण पर चर्चा में जवाब देने के दौरान प्रधानमंत्री ने पीठ पर बैठे सभापति को गलती से आदरणीय राष्ट्रपति कह कर संबोधित कर दिया। उनकी इस गलती के बाद विपक्षी सांसदों ने सभापति जगदीप धनखड़ को बधाई देनी शुरू कर दी कि आप राष्ट्रपति बन गए। प्रधानमंत्री ने भी माहौल को खुशनुमा बनाते हुए धनखड़ के लिए कई बार बधाई हो बोला। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री के मुंह से निकली यह बात धनखड़ के भविष्य के लिए शगुन साबित होती है या नहीं। कई हलकों में धनखड़ के अगले राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी की जाती रही है। हालांकि अभी तो यह दूर का मामला है पर धनखड़ के लिए इसे आगे का शुभ शगुन बनना तो कहा जा सकता है।

है डर...

महाराष्ट्र में भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाले घमासान की आशंका से डरी हुई भी है। ऊपर से मराठा आरक्षण के मुद्दे ने अलग भूचाल ला दिया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के आगे शिंदे सरकार को नतमस्तक होना पड़ा। कुनबी मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी के प्रमाण पत्र देने की आंदोलनकारियों की मांग शिंदे ने स्वीकार की तो सूबे के तमाम ओबीसी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई। ज्यादा मुखर सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के मंत्री छगन भुजबल दिखे। उन्होंने चेतावनी दी कि वे मराठों को ओबीसी आरक्षण में हिस्सा बांटने की नीति को सहन नही करेंगे। सरकार चाहे तो उन्हें अलग आरक्षण दे सकती है। पर ऐसी कवायद तो उद्धव सरकार ने पहले ही कर दी थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर रद्द कर दिया कि कुल आरक्षण कोटा 50 फीसद से ज्यादा नही हो सकता। पिछले हफ्ते भुजबल ने अहमदनगर में रैली कर खुलासा किया कि विरोधी ही नहीं उनकी अपनी पार्टी के मराठा नेता भी उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। पर वे भूल रहे हैं कि मैंने तो मंत्री पद से इस्तीफा पिछले साल 16 नवंबर को ही दे दिया था। शिंदे और फडनवीस के कहने पर बस खुलासा नही किया था। सूबे की सियासत में चल रही खींचतान के बीच संकेत मिल रहे हैं कि छगन भुजबल अजित पवार का साथ छोड़कर जल्द ही अपनी अलग पार्टी बनाने का एलान कर सकते हैं।

संसद में संन्यास

तेलगुदेशम पार्टी के सांसद जयदेव गल्ला ने राजनीति से अचानक संन्यास लेने का एलान करके हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि राजनीति में कारोबार जगत से जुड़े लोगों की व्यथा कितनी गहरी होती है। गल्ला आंध्रप्रदेश की गुंटूर सीट से लगातार दो बार लोकसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने सियासत से संन्यास लेने का एलान भी लोकसभा में ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए किया। गल्ला देश के चुनिंदा धनी सांसदों में हैं। वे एमरान ब्रांड की बैटरी व अन्य उत्पादों वाले अमर राजा समूह के मुखिया हैं। आंध्र में जगन रेड्डी की सरकार ने उन्हें तंग करने में कसर नही छोड़ी। हाई कोर्ट ने राहत न दी होती तो वाईएसआर कांग्रेस की सरकार तो उनका कारखाना ही बंद कर देती। बहरहाल गल्ला ने कहा कि राजनीति और कारोबार दोनों एक साथ ईमानदारी से नहीं चल सकते। उन्हें राजनीति में सच बोलने की सजा कारोबार में परेशानियों के रूप में भुगतनी पड़ी। सरकारी एजंसियों के राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग की शिकायत करना भी वे लोकसभा में नही भूले। फरमाया कि अब अपना सारा समय परिवार, कारोबार और दयानतदारी के लिए लगाएंगे।

संकलन : मृणाल वल्लरी

राजनीतिक यायावर

राजनीतिक यायावर नीतीश के पुनः भाजपा में आ जाने की घटना को बेशक एक अनावश्यक सम्मिलित हुआ प्रदूषण कहने से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय राजनीति में भाजपा एक सैद्धांतिक दल के रूप में स्थापित हो शनै शनै राष्ट्र को पुख्ता ही कर रही है। राष्ट्रीय राजनीति के इस हुजूम में गलियों से यायावरों का आना-जाना जारी रहेगा। भाजपा की स्थापना और उसका अभ्युदय एक विलंबित घटना है। अंततः झूठ का कोहरा तो छटना ही था। भारतीय राजनीति में भाजपा का वैचारिक विकल्प क्यों नहीं उपज रहा है? अब मतदाता राष्ट्रीय हित और क्षत्रपी राजनीति को वर्गीकृत करना सीख गया है। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय कांग्रेस को अदना निजी स्वार्थ के कारण रखना चाहते हैं। कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व बेशक भटकाव पर है। पर, उसका राष्ट्रीय अस्तित्व जिंदा रहना आवश्यक है। भटकते राहुल अपनी न्याय यात्रा पर जब बंगाल पहुंचते हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप ममता बनर्जी कांग्रेस की चालीस सीट भी नहीं आने का दावा करती हैं। खैर, वे खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए सौ सीट लाकर दिखा दें तो अच्छा होगा। वर्तमान राजनीतिक उथल-पुथल का कारण राष्ट्रीयता बनाम क्षेत्रीयता है। कांग्रेस राहुल गांधी के साथ वैचारिक पतन पथ पर है तो हिंसक राजनीति करने वाली ममता बनर्जी, खड़ाऊ राजनीति का बिहार, वंशवादी समाजवादी पार्टी दिल्ली तख्त को अस्थिर रखना चाहते हैं। राष्ट्र भूले नहीं, भारतीय मतदाता ने कांग्रेस को भी चार सौ से अधिक सीट दी थी। वैचारिक भटकाव को मूर्छा तो कहा जा सकता है, मौत नहीं।

-अरविंद पुरोहित, रतलाम, मध्यप्रदेश।

मजबूत हो सरकार

निश्चित रूप से मुकेश भारद्वाज आलेख के माध्यम से बिहार की राजनीति को केवल अवसरवादी राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति की समाप्ति की घोषणा की तरफ इशारा कर रहे हैं। और, नीतीश कुमार हर बार तीसरी शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व दिखाते आए हैं। जनता हमेशा मशीन के नीले बटन को दबाकर अपने आप को ठगा ही महसूस करती रही है। बुनियादी जरूरत को राजनेता केवल हंसी ठिठोली और अनर्गल बयानबाजी देकर तिलांजलि देते आए हैं। अब समय आ गया है कि जनता जनार्दन अपने वोटों के जरिए मजबूत इरादों वाली सरकार को ही चुने चाहे आगे कितना भी मजबूत राजनेता और रसखूदार हो।

-महेश आचार्य, नागौर।

आपके पत्र

कीर्तिमान में कीर्ति?

बीते दिनों बिहार में हुई राजनीतिक हलचल ने मौसम को भी शर्मा दिया। सत्ता के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं यह बात तो हजम हो सकती है लेकिन जनता के जनादेश को धता बताकर अपनी रोटी सेंकने का बहुत ही भद्दा मिसाल बिहार में कायम हुआ है। बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार की यह मजबूरी है या अपनी राजनीतिक जमीन को पैदावार बनाए रखने की जुगत? क्या नीतीश इस फसल को काट पाएंगे ये उससे भी बड़ा सवाल है!

-जफर अहमद, मधेपुरा, बिहार।

आदर्श की अनदेखी

राम राज्य के आदर्शों पर चलने को संकल्पित देश को बिहार राज्य ने राजनीति में नई हवा दे दी है, जिसे राजग के सबसे बड़े दलों में से एक भाजपा भी सहज स्वीकार करते हुए आगे चलने को प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ समाजवाद के सैद्धांतिक सिद्धांत को बचाए रखने की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक कार्यशैली ने प्रदेश की कई 'भोजपुरी कहावतों' को पुनर्जन्म दे दिया है। ये कहावतें नीतीश कुमार को सत्ता के लालच में राजनीतिक दल-बदल के परिदृश्य का पर्याय बनाकर सोशल मीडिया की दुनिया में तैर रही हैं। एक समय था जब किसी राजनेता के इतिहास को खंगालने के लिए पुराने अखबार, पत्रिका और किताब का सहारा लिया जाता था। लेकिन, सूचना प्रौद्योगिकी ने बदलाव की ऐसी लकीर खींची है जो किसी भी राजनेता की जीवनी की अमर कहानी इंटरनेट के संग्रहालय में हमेशा के लिए सुरक्षित रख देती है। जिन्हें तलाशने के लिए अंगुली के एक क्लिक पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का सफर स्क्रीन पर जीवंत हो उठता है। नीतीश कुमार की राजनीतिक इंजीनियरिंग ही है जो जद (एकी) को कभी भी पूर्ण बहुमत से सत्ता की कुंजी नहीं दिला पाए, लेकिन फिर भी सत्ता के शीर्ष पद मुख्यमंत्री की शपथ नौवीं बार ले चुके हैं। यह सच है कि उनका राजनीतिक सफर बेदाग रहा है, लेकिन उनकी अवसरवादिता उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर चुकी है। फिर भी वह सामने वाले विपक्षी दलों को कभी परिवारवाद तथा कभी राष्ट्रवाद पर घेरते नजर आते हैं। कुछ समय बाद ऐसा भी आएगा जब सभी दल मिलकर सवाल करेंगे कि क्या सत्ता के लालच में एक मुख्यमंत्री, पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए त्यागपत्र देते हैं और फिर से उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तब क्या उन्हें अवसरवादी राजनेता कहा जाएगा? क्या यह एक परिवारवाद ,राष्ट्रवाद से कमतर है जो उन्हें जनता चुनती भी नहीं है? लेकिन फिर भी जोड़-तोड़ व दल-बदल के राजनीतिक दांव-पेच से वे बार-बार सत्ता हासिल कर बैठते हैं?

-नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, बिहार।

करवट का करतब

राजनीति करवट लेती रहती है, यह बात तो सिद्ध है, लेकिन बिहार में करवट का जो करतब खेला गया वह इतिहास में किस खाते दर्ज होगा इसके लिए भी माथापच्ची करनी होगी। एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए 'पलटू' शब्द का सार्वजनिक इस्तेमाल होने लगे, और वह आदर्शों के आंगन में भी खड़े हों यह विडंबना भी इस समय को देखना था। जिस बिहार से राजनीतिक आदर्श की बयार बही थी वहीं से अवसरवादिता की आंधी भी उठती दिखी है जो राजनीति में शुचिता की बात करने वालों की आंखों को सिर्फ धूल धूसरित कर रही है।

-मीना धानिया, सिरसपुर।

भटकी मर्यादा

अयोध्या से बिहार तक के सफर में ही रघुकुल की मर्यादा भूल जाने वालों को लिपिबद्ध करने के लिए मुकेश भारद्वाज का शुक्रिया।

-अंकुर सिंह, गाजियाबाद।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com